● वर्ष-3
● अंक-39
रायपुर, शनिवार
23 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

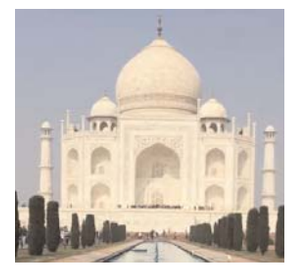

पेज-6›› भारत के पर्यटन स्थल

चीन को मुंहतोड़ जवाब, खेल मंत्री का दौरा रद्द

अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने का मामला गरमाया

नई दिल्ली। हांगझोऊ एशियाई खेलों से पहले भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। दरअसल, खेलों से पहले चीन की एक नापाक हरकत सामने आई। उसने हांगझोऊ एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के तीन वूशु खिलाड़ियों को अंतिम क्षणों में वीजा नहीं दिया। ये वही तीन खिलाड़ी हैं, जिनके साथ चीन में कुछ महीने पहले हुए यूनिवर्सिटी गेम्स में भी चीन सरकार द्वारा बदसलूकी की गई थी और उन्हें नत्थी वीजा दिया गया था। अब फिर से इन तीनों को चीन ने सामान्य वीजा जारी नहीं

किया। ऐसे में ये तीनों भारत की वूशु टीम के साथ हांगझोऊ रवाना नहीं हो सके। अब यह मामला गरमा गया है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले एशियाई खेलों के लिए चीन का दौरा करने वाले थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपनी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एशियाई खेलों का आधिकारिक आगाज 23 सितंबर को होगा। विवाद के बीच ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष वेई जिझोंग ने इस बात से इनकार किया कि चीन ने खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वूशु एथलीटों ने इस वीजा को स्वीकार नहीं किया है।

चीन की ओर से फिर से नत्थी वीजा देने की कोशिश

खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) बुधवार को इन खिलाड़ियों के वीजा के प्रयास में लगे रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक खिलाड़ी को एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि खेल मंत्रालय, आईओए ने इन तीनों खिलाड़ियों को वीजा जारी करने के लिए आयोजन समिति से बात की तो उनसे कहा गया कि इन खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी होगी। इसके लिए खेल मंत्रालय तैयार नहीं था। ऐसे में तीनों अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी तेगा ओनिलु, लामगु मेपुंग और वांगसू न्येमान टीम के साथ नहीं जा पाए। बाकी टीम, जिसमें 10 खिलाड़ी और थे, हांगझोऊ के लिए रवाना हो गई। इससे पहले भी 26 जुलाई को विश्व यूनिवर्सिटी खेलों के लिए इन्हीं तीनों खिलाड़ियों को चीन ने नत्थी वीजा जारी कर दिया था। इसके विरोध में भारत सरकार ने पूरी वूशु टीम को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया था।

तीनों वूशु खिलाड़ियों को नहीं मिला मान्यता कार्ड

वांग्सू न्येमान को तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। उनके पास एशियाई खेलों की आयोजन समिति से जारी एक्रिडिटेशन (मान्यता कार्ड) भी था। खिलाड़ियों को एक्रिडिटेशन पर ही वीजा जारी किया गया है। वांगसू को एयरपोर्ट पर एयरलाइंस ने बताया कि वह केवल हांगकांग तक जा सकती हैं। उससे आगे का उनका वीजा नहीं है। तेगा और मेपुंग के अलावा सूरज को एशियाई खेलों की आयोजन समिति ने ई एक्रिडिटेशन जारी किया था। जब इन खिलाड़ियों ने अपना एक्रिडिटेशन कंप्यूटर से निकालना चाहा तो वांगसू, तेगा और मेपुंग के कार्ड नहीं आए, जबकि सूरज को वीजा जारी कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इनको कार्ड दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। एक बार जब एथलीटों को आयोजन समिति से एक्रिडिटेशन कार्ड प्राप्त हो गए, तो इसका मतलब था कि उन्हें एशियाई खेलों के लिए यात्रा करने की मंजूरी मिल गई।

भारतीय के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा- भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व-निर्धारित तरीके से,अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझोऊ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। भारत दृढ़ता से अधिवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के

साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। अरिंदम बागची ने कहा- चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के निशान के रूप में, भारत के सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने एशियाई खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है।

एनडीए का हिस्सा बनी जद (एस)

नईदिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की जनता दल (सेक्युलर) शुक्रवार को औपचारिक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से एचडी कुमारस्वामी की मुलाकात के बाद यह निर्णय हुआ है। कर्नाटक की राजनीति और 2024 चुनाव को लेकर इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा सकता है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। मुझे खुशी है कि जद (एस) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से विकास कार्य कर रहे हैं, कोई भी पार्टी एनडीए में शामिल होने से इनकार नहीं करेगी...मैं भी उनका (जेडीएस) स्वागत करता हूं.% आगामी चुनाव में एनडीए एक बार फिर सत्ता में आने वाली है. हम कर्नाटक में सभी लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। एनडीए को मजबूत बनाने के लिए जेडीएस आज औपचारिक रूप से एनडीए गठबंधन में

शामिल हो गई है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं... संसदीय बोर्ड और जेडीएस सीटों के बंटवारे पर फैसला लेंगे। एचडी कुमारस्वामी कहते हैं, आज औपचारिक तौर पर हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर चर्चा की. हमने शुरुआती मुद्दों पर औपचारिक तौर पर चर्चा की है...कोई मांग नहीं है (हमारी तरफ से)। दोनों दलों के बीच गठबंधन पर बातचीत तब से सुर्खियों में है, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा, जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, ने कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए जद (एस) के साथ समझौता करेगी। और क्षेत्रीय दल कर्नाटक में चार लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें कुल 28 निर्वाचन क्षेत्र हैं। भाजपा ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनावों में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि उसके समर्थन वाली निर्दलीय (मांड्या से सुमलता अंबरीश) ने एक सीट जीती थी। कांग्रेस और जद(एस) ने एक-एक सीट जीती। इस साल मई में हुए 224 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें मिलीं।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया, सूर्या फॉर्म में लौट

मोहाली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पांच विकेट से हरा दिया है। मोहाली में खेले गए वनडे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर 276 रन बनाए। डेविड वॉर्नर ने 52, जोश इंग्लिस ने 45 और स्टीव स्मिथ ने 41 रन की पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने पांच विकेट लिए।

जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को

बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 142 रन जोड़े। ऋतुराज ने 71 रन और शुभमन गिल ने 74 रन की पारी खेली। वहीं, सूर्यकुमार यादव 50 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केएल राहुल ने 58 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 49वें ओवर में शॉन एबॉट की गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई।भारत ने मोहाली में 1996 के बाद पहली बार यानी 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में जीत हासिल की है। यह दोनों के बीच इस मैदान पर छठा मैच था। इसमें से भारत ने दो और ऑस्ट्रेलिया ने चार मुकाबले जीते हैं। 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2006, 2009, 2013 और 2019 में खेले गए वनडे मैचों में हराया। यानी इस मैदान पर पिछले चार वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे।सीरीज का दूसरा वनडे 24 सितंबर को इंदौर में खेला जाएगा। वहीं, तीसरा वनडे 27 सितंबर को राजकोट में खेला जाएगा। यह दोनों टीमों के लिए विश्व कप से पहले आखिरी सीरीज है। इस सीरीज के लिए दोनों टीमें अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना चाहेगी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर-1

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज शुक्रवार (22 सितंबर) को शुरू हुई। टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 276 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 48.4 ओवर में 281 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया। वह टी20 और टेस्ट में पहले ही शीर्ष पर था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर-1 बन गया है। केएल राहुल की कप्तानी में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया इतिहास रच दिया। वह एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा किया था।

चक्रधर समारोह के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ सहित शहर के स्थानीय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इस बार का चक्रधर समारोह खास रहा। तीन दिन के आयोजन में रिकॉर्ड एक हजार से अधिक कलाकारों की प्रस्तुति दी। स्थानीय प्रतिभाओं, बाल कलाकारों के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोर चुके कला दिग्गजों ने समारोह में शिरकत की। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के 60 कलाकारों के दल के अलग-अलग विधाओं में प्रस्तुतियां दी गई।

प्रमुख समाचार

जी20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता का श्रेय सभी को: मोदी

नई दिल्ली।भारत की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने में उनकी अटूट प्रतिबद्धता और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए, प्रधान मंत्री

नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत मंडपम में %टीम जी20% के साथ मुलाकात की। इस दौरान, प्रधानमंत्री जी20 शिखर सम्मेलन के सुचारू कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोगों के सम्मान में एक भव्य रात्रिभोज भी रखा गया। टीम जी-20% के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जी-20 का सफल आयोजन हुआ। देश का नाम रोशन हुआ। चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ सुनने को मिल रही है। इसके पीछे जिनका पुरुषार्थ है, जिन्होंने दिन रात इसमें खपाए हैं और जिनके कारण ये सफलता प्राप्त हुई वे आप सब हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप में से ज्यादातर वे लोग होंगे जिन्हें इससे पहले इतने बड़े कार्यक्रम का, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी का अवसर ही नहीं आया था। आपको आयोजन की कल्पना भी करनी थी और समस्याओं के विषय में भी सोचना था।

बसपा सांसद दानिश अली से मिले राहुल गांधी

नई दिल्ली।कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात की। यह बैठक उस दिन हुई जब लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ आपत्तीजनक टिपण्णी की थी। बीएसपी सांसद दानिश अली से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भाजपा नेता की टिप्पणी संसद के निचले सदन में चंद्रयान-3 की सफलता पर चर्चा के दौरान आई। कार्यवाही के दौरान बिधूड़ी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ये उग्रवादी , ये उग्रवादी है, उग्रवादी है, ये उग्रवादी है। दानिश अली लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। रक्षा मंत्री और लोकसभा के उप नेता राजनाथ सिंह ने बिधूड़ी की टिप्पणी पर खेद जताया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर राजनीतिक बवाल जारी है। सपा प्रमुख मायावती ने कहा कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालाँकि स्पीकर ने रिकार्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है व वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी।

अमृतानंदमयी को मिला वर्ल्ड लीडर अवार्ड

नई दिल्ली। प्रशंसकों और अनुयायियों के बीच अम्मा के नाम से लोकप्रिय देवी को वैश्विक शांति, आध्यात्मिकता और करुणा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस सम्मान के लिए उनका चुनाव हुआ है। बीजीएफ और एमडीआई

के अनुसार, अम्मा की गहन आध्यात्मिकता, मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिलाया है। इसमें कहा गया है कि भारत में 2023 जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान जी20 नागरिक समाज के नेताओं वाले सिविल 20 एंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, अम्मा ने जी20 के मोटो, %यू आर द लाइट% को मूर्त रूप दिया। यह घोषणा 31 जुलाई को जयपुर, भारत में ष्ट20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। एजेंसी के अनुसार बोस्टन ग्लोबल फोरम मैसाचुसेट्स में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है, जो शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करने वाले नेताओं, विद्वानों, नीति निर्माताओं और व्यापारिक नेताओं को बुलाने के लिए समर्पित है।

जन आक्रोश यात्रा के दौरान आपस में ही भीड़ गए कांग्रेसी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि, दोनों पार्टियों में गुटबाजी भी समय-समय पर दिख जा रही हैं।

मध्य प्रदेश के पवई क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ने लगे, जब उनमें से कुछ ने मुकेश नायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। घटना उस वक्त हुई जब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा गुरुवार को दमोह से पवई विधानसभा के सिमरिया पहुंची. वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकेश नायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके साथ ही उनके हाथों में %मुकेश नायक मुर्दाबाद% जैसे नारे लिखी तख्तियां भी थीं। बताया जा रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ता मुकेश नायक से नाखुश थे। उनकी मांग है कि पार्टी वहां से किसी स्थानीय कार्यकर्ता को मौका दे। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हालांकि, पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। झड़प के दौरान अरुण यादव और सीपी

कृष्ण जन्मभूमि मामला, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (एससी) ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद

परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया था या नहीं। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसने मथुरा के एक दीवानी न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता न पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्होंने मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा उठाए गए मुकदमे की विचारणीयता के मुद्दे पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया था। ट्रस्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने मथुरा के दीवानी न्यायाधीश को मुकदमे के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर फैसला करने से पहले कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर फैसला करने का निर्देश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

कुर्सी बचाने के लिए अपने ही बनाये गड्ढे में गिर गये जस्टिन ट्रूडो

बिक्रम उपाध्याय

जस्टिन ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और वह औगे भी रहना चाहते हैं। उनके पिता पियरे ट्रूडो 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। पर कनाडा की जनता नहीं चाहती कि जस्टिन अब और प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसी साल 18 से 23 अगस्त के बीच में अबैकस डाटा ने एक नेशनल सर्वे किया था जिसमें 2,189 युवाओं ने भाग लिया था। सर्वे में भाग लेने वाले 56 प्रतिशत युवकों का सीधा कहना था कि अब जस्टिन को अपने पद से उतर जाना चाहिए।

जस्टिन को भी मालूम है कि मुद्रा स्फीति बढ़ने, मकान बहुत महंगे होने और कंजरवेटिव पार्टी का ग्राफ तेजी से बढने के कारण उन पर पद छोड़ने का दबाव है और एक हफ्ता पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि क्या वे पद छोड़ रहे हैं? तब ट्रूडो ने ना में जवाब दिया था और कहा था कि उनके पास बहुत से महत्वपूर्ण काम करने को है। भारत पर सनसनीखेज इल्जाम लगाकर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत ही संभवत: उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था जो उन्होंने किया है।

कनाडा में अभी आम चुनाव होने में दो साल का समय है। इन हालात में ट्रूडो के लिए इतने दिन बने रहना संभव नहीं था, क्योंकि ट्रूडो लगातार विफल हो रहे हैं। एक उर्जावान नेता की बजाय वे उलझे हुए नेता लग रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी को तलाक देने की घोषणा भी की है, जिसका कनाडा के कंजरवेटिव नेताओं ने खूब मजाक भी उड़ाया था।

भारत पर आरोप लगाकर कनाडाई जनता

का समर्थन प्राप्त करने के जोखिम भरे कदम को उठाने से पहले वह राजनीतिक कलाबाजी को आजमा चुके हैं। इसी साल 26 जुलाई को उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव कर सात लोगों को शामिल किया था। पर यह बदलाव भी काम नहीं आया और कनाडा की जनता का गुस्सा उनके प्रति कम नहीं हुआ, जिसका सबूत केबिनेट में बदलाव के बाद आया नेशनल सर्वे रहा।

ट्रूडो परिवार एवं खालिस्तानी आतंकवादियों का संबंध लगभग 40 साल पुराना है। 23 जून 1985 को एयर इंडिया का विमान एआई 182 मांट्रियाल से लंदन होते हुए बंबई आ रहा था। उसमें 329 लोग सवार थे। बीच आसमान में इस जहाज में विस्फोट हुआ और सभी लोग मारे गए। इतिहास में इसे कनिष्क एयर इंडिया बॉबिंग के नाम से इसे दर्ज किया गया। इस बम कांड में खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के लीडर तलविंदर सिंह परमार का नाम आया। यह आतंकवादी भारत में 1981 में दो पुलिसवालों की हत्या कर कनाडा फरार हो गया था।

1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब जस्टिन ट्रूडो के पिता और कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे से अनुरोध किया था कि वह भारत में वांछित परमार को भारत को सौंप दे, लेकिन तब सीनियर ट्रूडो ने यह कहकर उस आतंकवादी को भारत को सौंपने से इंकार कर दिया कि उनका देश भारत के साथ प्रत्यार्पण की संधि से नहीं बंधा है इसलिए वह परमार को नहीं भेजेगा। हालांकि परमार बाद में भारत आया और 1992 में पंजाब पुलिस से मुटभेड़ में मारा भी गया लेकिन तब से लेकर ट्रूडो परिवार और खालिस्तानी नेताओं के बीच मधुर संबध चले आ रहे हैं।

कनाडा की 3.82 करोड़ जनसंख्या में सिख आबादी के हिसाब से 2.1 प्रतिशत हैं पर कुछ जगह इनकी संख्या छह प्रतिशत से भी अधिक है। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया जहां ट्रूडो का सबसे अधिक समय बीता है, वहां सिखों की आबादी छह प्रतिशत है। वेंकूवर, टोरंटो और कैलगेरी में बड़े बड़े गुरूद्वारे हैं। ये गुरूद्वारे कनाडा की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन गुरूद्वारों में कनाडा की लिबरल और कंजरवेटिव दोनों पार्टियों की पैठ है। कई सिख नेता इन्हीं गुरूद्वारों के प्रभाव से कनाडा की राजनीति में अपनी पकड़ बना के रखते हैं।

2019 में कनाडा में चुनाव प्रचार के दौरान ही जस्टिन के समर्थन के बदले सिखों के स्वेच्छाचार का मुद्दा उठा था। तब कुछ पार्टियों ने यह नारा दिया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ लगाम लगानी चाहिए। पर ट्रूडो की पार्टी ने सिखों से कुछ और वायदा किया। उस समय वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के कानूनी सलाहकार बलप्रीत सिंह ने कहा था- यह कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव का क्षण है।

सुकमा में 25 साल बाद जगमग हुए नक्सल प्रभावित सात गांव, बिजली सेवा हुई बहाल

सुकमा। राजधानी रायपुर से 400 किमी दूर सुकमा जिले के सात गांवों में 25 साल बाद बिजली आई है। इन सात गांवों को नक्सली दंश के कारण बिजली से वंचित होना पड़ा था।1990 के दौरान इन गांवों में बिजली की कनेक्टिविटी थी।लेकिन नक्सलियों ने गांवों के पास मौजूद ग्रिड लाइन और बिजली के खंबों को नुकसान पहुंचाया।इसके बात इन क्षेत्रों में नक्सली आतंक इतना बढ़ा कि किसी भी सरकार ने दोबारा इन गांवों में बिजली सेवा बहाल करने की कोशिश नहीं की।लेकिन बीते दिनों इन सात गांवों के निवासियों को 25 साल बाद फिर से बिजली की सुविधा मिल गई।

इन सात गांवों में 342 परिवार रहते हैं। जिनमें से कुछ के पास बिजली को लेकर सिर्फ सोलर एनर्जी का ही विकल्प था।सोलर एनर्जी के कुछ घरों में बिजली तो थी, लेकिन मौसम खराब होने और मेंटनेंस के अभाव में ये सुविधा भी कुछ महीनों बाद ठप हो गई।इसके बाद से ही ग्रामीण बिजली को तरस रहे थे। सुकमा कलेक्टर हरिस एस के मुताबिक सात गांवों डब्बाकोंटा, पिडमेल, एकलगुडा, दुरामंगु, तुम्बांगु, सिंगनपाड़ और डोकपाड़ में बिजली की सुविधा पहुंचाई गई है।

सुकमा कलेक्टर ने कहा सरकार और प्रशासन लोगों, विशेषकर अंतिम व्यक्ति तक राशन, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के

लिए प्रतिबद्ध है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे। सात गांवों में विद्युतीकरण से लगभग 342 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

इस क्षेत्र में कई गांवों को अब भी बिजली का इंतजार है।जिसके लिए सरकार की मदद से प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।सुरक्षा के लिहाज से भी इस क्षेत्र में बिजली की काफी ज्यादा जरुरत थी। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सली क्षेत्र में छह पुलिस शिविर स्थापित करने से दूरदराज के क्षेत्रों में विकास को गति मिली है। पिडमेल, दुब्बाकोंटा, टोंडामरका, दुब्बामरका, एल्मागुंडा, करिंगुंडम में पुलिस शिविरों की स्थापना के बाद, ग्रामीणों को अब उनकी बुनियादी सुविधाएं और सुविधाएं वापस मिल रही हैं। 1990 के दशक के अंत तक इन गांवों में बिजली कनेक्टिविटी थी।नक्सलियों ने बिजली के खंबों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण ग्रामीण लगभग 25 वर्षों तक नियमित बिजली आपूर्ति से वंचित रहे।

सुंदरराज पी के मुताबिक डुब्बाकोंटा और पिडमेल भेजी-चिंतागुफा के कोने में है। दुब्बाकोंटा और पिडमेल दोनों ही जगहों पर पुलिस कैंप हैं। आरआरपी (सड़क आवश्यकता संयंत्र)-1 योजना के तहत ब्लैक-टॉप सड़क भी तेज गति से बनाई जा रही है।जिसके बाद उन गांवों तक भी कनेक्टिविटी हो जाएगी जहां पर कच्ची सड़क के कारण सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी।

सुकमा में बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता जोसेफ केरकेट्टा के मुताबिक भौगोलिक स्थिति और नक्सलियों की मौजूदगी के कारण सात गांवों में बिजली लाइन बिछाना एक कठिन काम था। विद्युत सामग्री को चिन्हित स्थल तक पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ये सभी गांव घने जंगलों के बीच हैं। कई गांव अत्यधिक संवेदनशील इलाकों में हैं। इस क्षेत्र में श्रमिकों की उपलब्धता कठिन है। जिला प्रशासन के लगातार प्रयास से यह संभव हो पाया है। आज यहां के ग्रामीण अंधकार से मुक्ति का जश्न मना रहे हैं।

बालोद में फिर दंतैल हाथी की दस्तक दर्जन भर गांवों को किया गया अलर्ट

बालोद। बालोद जिले में एक बार फिर से दंतैल हाथी ने दस्तक दी है। वन विभाग लगातार स्कीम मॉनिटरिंग कर रहा है धमतरी के वन क्षेत्र से इस बार हाथी ने जिले में प्रवेश किया है। बालोद जिले के गुरुर वन परिक्षेत्र के बालोदगहन परिसर स्थित वन कक्ष क्रमांक दो,तीन आरएफ क्षेत्र में मौजूद है और वन विभाग टीम भी पीछे- पीछे घूम रही है। आपको बता दें कि लगभग तीन से चार वर्ष हो गए हाथियों की टीम बालोद जिले में सक्रिय बनी है। कभी आते हैं कभी जाते हैं और अब तक आधा दर्जन व्यक्तियों की जान भी यह दंतैल हाथी ले चुके हैं।

फसलों को पहुंचाया नुकसान

हाथियों ने खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है जिसके बाद मुआवजा प्रकरण भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि कार्य जोरों पर हैं और धान की फसलें पूरी तरह खड़ी हुई हैं। ऐसे में हाथी के दस्तक से किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

दर्जन भर गांवों में हाई अलर्ट

हाथी की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने बोरिदकला, मुडखुसरा सहित कुल 11 गावों में अलर्ट जारी कर दिया है। क्षेत्र के ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने व सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है।

अब तक 163 घर तोड़े

हाथी लगभग दो से तीन वर्षों से बालोद जिले में सक्रिय हैं और अब तक हाथियों द्वारा 163 मकानों को क्षतिग्रस्त किया गया है और आधा दर्जन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सभी मृतक वनांचल क्षेत्र के बताए जा रहे हैं वन विभाग लगातार लोगों को जागरुक कर रहा है।

एमसीबी में धर्मांतरण के खिलाफ श्री बजरंग सेना की दहाड़ रैली

लालच देकर कन्वर्जन का लगाया आरोप

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल से जुड़े संगठन अपने-अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करके जनता का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस कड़ी में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के खड़गवां क्षेत्र में श्रीबजरंग सेना ने धर्मांतरण के खिलाफ रैली निकाली। बजरंग दल की इस दहाड़ रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।

लालच देकर धर्मांतरण करने का आरोप- रैली में शामिल हुए संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि जिले के अंदर तेज गति से भोले-भाले आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। श्रीबजरंग सेना के जिलाध्यक्ष सूरज देवांगन समेत संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि जिले के अंदर हो रहे धर्मांतरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी श्रीबजरंग सेना ने दी है। इस रैली में जिला अध्यक्ष सूरज देवांगन और जिला उपाध्यक्ष विजय साहू के साथ महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह भी शामिल हुई थी।

भारती सिंह, प्रदेशाध्यक्ष,महिला विंग ने कहा श्रीबजरंग सेना की इस दहाड़ रैली के आह्वान के बाद भी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।

धर्मांतरण कराने वालों को खुली चेतावनी- इस रैली में धर्मांतरण को लेकर हुंकार भरते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र के अंदर मिशनरी के माध्यम से लोगों को लालच देकर बरगलाया जा रहा है। जिसे देखते ही देखते कई लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है। यदि इस रैली के बाद भी धर्मांतरण का खेल जारी रहा तो आने वाले दिनों में श्रीबजरंग सेना धर्मांतरण कराने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन करेगी।

शक्कर कारखाना के ठेका कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

क बीर धाम। कबीरधाम के ग्राम राम्हेपुर स्थित प्रदेश के पहले भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के ठेका व अनियमित कर्मचारी शुक्रवार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ये कर्मचारी कारखाना के मेन गेट के सामने टेंट लगाकार बैठे हैं।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना श्रमिक कल्याण संघ के अध्यक्ष रामचरण लांझी ने बताया कि कारखाना के श्रमिक बीते कई वर्ष से अपनी नियमितीकरण और रिकवरी के साथ चार प्रमुख मांग करते आ रहे हैं। दर्जनों बार ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके बाद अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। कारखाना में बीते 10 वर्ष से अधिकतर कर्मचारी संविदा, ठेका के रूप में काम कर रहे हैं। कम वेतन की भी समस्या है। इन्हीं मांगों को लेकर कारखाना में पेराई सत्र शुरू होने से एक माह पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए है।

वहीं, इन कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने के बाद शुक्रवार को दोपहर 12 बजे बोड़ला एसडीएम, तहसीलदार व कारखाना के अधिकारी पहुंचे हुए थे। कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने अपील की गई। बता दें कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना प्रदेश का पहला कारखाना है। इस कारखाना की शुरूआत वर्ष 2002-03 में हुई है। कारखाना में करीब 11 हजार किसानों से हर साल लगभग 4 लाख एमटी गन्ना की खरीदी की जाती है। यहां का पेराई सीजन हर वर्ष नवंबर माह से लेकर मार्च माह तक चलता है।

पद का दुरुपयोग करते हुए नौ जगहों पर कब्जा

बालोद। बालोद जिले के ग्राम मुजगहन के सभी ग्रामीण आज ग्राम पटेल के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट के सामने लगभग तीन घंटे तक प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पटेल मोहम्मद हनीफ द्वारा पटेल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नौ जगहों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया और जमीन को बेच भी दिया गया। इस दौरान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच जमकर तनातनी भी हुई।

कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। अंत में अपर कलेक्टर ने मोर्चा संभालते हुए शाम तक पटेल पद से निष्कासन करने संबंधित आदेश जारी करने की बात कही तब ग्रामीण शांत हुए। परंतु बिना निष्कासन पत्र लिए ग्रामीण वहां से रवाना नहीं हुए आसपास ही बैठे रहे।

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पटेल मोहम्मद हनीफ जमीनों को अपने परिजनों के नाम से रखता है। कभी भाई के नाम से कभी बहन के नाम से कभी भतीजे के नाम से तो कभी और किसी के नाम से पहले जमीन पर कब्जा करता है फिर ना जाने कैसे फर्जी रूप से जमीन का पट्टा बनवा लेता है। ग्रामीण अपनी जायज मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भाजपा व कांग्रेस का भी दूर से ही साथ मिलता हुआ नजर आया। एक तरफ पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा वहां पर दूर से उनकी भीड़ को समर्थन दे रहे थे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार एवं मंडल अध्यक्ष प्रेम साहू भी समर्थन में पहुंचे थे। पूर्व विधायक भैया राम सिंह की पहल पर दोनों पक्षों में बात बन पाई।

डेंगू को लेकर बुलाई बैठक में भाजपा-कांग्रेस का हंगामा

रायगढ़। पिछले कई हफ्तों से रायगढ़ में डेंगू बीमारी से लगभग ढाई सौ से अधिक लोग बीमार हुए हैं। 3 लोगों ने डेंगू से अपनी जान गंवा दी। इस बीमारी से निपटारे और कार्य योजना के लिए शहर के एक धर्मशाला में सर्व समाज की बैठक की गई, जो राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखा। अग्रसेन भवन में बुलाई गई सर्वसमाज की बैठक में ये तय होना था कि रायगढ़ कलेक्टर से मिलकर इस गंभीर विषय पर कार्य योजना बनाई जाएगी। शहर के जो हॉटस्पॉट हैं वहां विशेष टीम से सफाई, दवा का छिड़काव, फॉगिंग कराने को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन धर्मशाला से कलेक्ट्रेट पहुंचते तक सर्व समाज की बैठक भाजपा कांग्रेस के हंगामे में बदल गई। डेंगू को छोड़कर आपस में भिड़े भाजपा कांग्रेस नेता- इस बैठक में भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी शामिल होने वाले थे। लेकिन उन्हें आने में देर हो रही थी। जिस पर भाजपा के कुछ नेताओं ने इंतजार करने की बात कही। इस पर सर्व समाज की बैठक में मौजूद कुछ लोग भड़क गए। बताया जा रहा था कि वे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे। जिसके बाद सर्व समाज की बैठक दलगत भीड़ में तब्दील हो गई। नतीजा ये हुआ कि कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद भाजपा और कांग्रेस के लोग आमने सामने हो गए। भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट परिसर में शासन प्रशासन, नगर निगम, शहर विधायक सबके खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस अधिकारी के चैंबर में घुसने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद माहौल और तनाव पूर्ण हो गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आज मनाया जायेगा आयुष्मान भारत दिवस

बेमेतरा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पांचवी वर्षगांठ व आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला बेमेतरा में कार्यशाला का आयोजन 23 सितम्बर 2023 को आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर किया जायेगा । कार्यशाला का उद्देश्य योजना का प्रचार प्रसार किया जाना है। इस अवसर पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला चिकित्सालय बेमेतरा में हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड दिये जाने के साथ योजना की जानकारी आम जन को दिया जायेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 50 हजार से 5 लाख तक पंजीकृत चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार सुविधा प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पडने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है।

बस डिवाइडर से टकराई बाल-बाल बचे यात्री

जगदलपुर। जगदलपुर से बैलाडीला यात्रियों को लेकर निकली बस शुक्रवार की सुबह डिमरापाल मेडिकल कॉलेज से पहले अशोका लीलैंड के सामने डिवाइडर में जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 24 से अधिक यात्री सही सलामत रहे। यात्रियों को दूसरी बस की मदद से रवाना किया गया। वहीं, बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस का सामने का टायर फटने के कारण ये हादसा हुआ है। बताया जा है कि कांकेर रोडवेज की बस जगदलपुर से बैलाडिला यात्रियों को लेकर निकली हुई थी। शुक्रवार की सुबह करीब छह बजे के लगभग जैसे ही बस मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से कुछ दूरी पहले अशोका लीलैंड के पास पहुंची कि यात्री बस के सामने का टायर फटने से चालक ने अपना नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर में जा टकराई। इस हादसे में बस में बैठे यात्रियों को किसी भी तरह से कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों को दूसरे बस की मदद से बैलाडिला रवाना किया गया। घटना की जानकारी लगते ही परपा पुलिस मौके पर पहुंची।

मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने किया रक्तदान

जगदलपुर। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में गणेश चतुर्थी के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही करीब 50 छात्रों ने रक्तदान किया। बताया जा रहा है कि मेकाज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। इसी के साथ रक्तदान शिविर लगाया गया। इन छात्र छात्राओं का कहना था कि मेकाज में रोजाना बस्तर जिले से ग्रामीण अपना उपचार करने के लिए आते रहते हैं। जिनमें से कई ग्रामीणों को रक्त की जरूरत होती है। ऐसे में छात्र-छात्राओं के द्वारा किया गया रक्तदान आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के काम आएगा।

स्कूली वैन में आग लगने से मचा हड़कंप, एक बच्ची झुलसी

बिलासपुर। बिलासपुर के तखतपुर इलाके में एक स्कूली वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। वैन में कई बच्चे सवार थे, इनमें से एक बच्ची झुलस गई। जिसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तखतपुर बालक हाईस्कूल के पास संचालित आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वेन और अन्य साधनों से स्कूल जाते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बच्चे स्कूली वैन में स्कूल जा रहे थे। जब वैन गुरुद्वारा रोड ताम्रकार ज्वेलर्स के पास पहुंची थी तो अचानक उसमें आग लग गई। हालांकि आसपास के लोगों ने तत्काल पानी डालकर वेन में लगी आग को बुझा दिया। वहीं, वैन में आग लगते ही सभी बच्चों को तुरंत बाहर निकाला गया। इससे बडी घटना होते-होते बच गई। हालांकि, एक छात्रा आराध्या केशरवानी पिता अतुल केसरवानी निवासी जनकपुर तखतपुर इस घटना में झुलस गई है। जिसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

एसबीआई की मेन ब्रांच में अलसुबह लगी भीषण आग

भिलाई नगर। बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर-1 में स्थित एसबीआई के मेन ब्रांच में शुक्रवार की अलसुबह आग लग गई। ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भिलाई के सेक्टर-1 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में अलसुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि बैंक के फस्ट फ्लोर पर स्थित कम्प्यूटर रूम में सबसे पहले आग लगी और फैलने लगी। सूचना मिलते ही भिलाई इस्पात संयंत्र की तीन गाडियां आग पर काबू पाने की कोशिश में सुबह से लगी रहीं। टीम में 20 से अधिक दमकल कर्मी और बैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

प्रियंका के जरिए महिला और युवा वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस

दुर्ग-भिलाई। गुरुवार को प्रियंका गांधी ने दुर्ग में महिला समृद्धि सम्मेलन में शिरकत की। प्रियंका गांधी के दौरे से महिला वोटरों को साधने की कोशिश की गई। सम्मेलन के दौरान प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की स्व सहायता समूह और अन्य महिला समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। उनसे चर्चा कर उनके आमदनी और कामों के बारे में जानकारी ली। प्रियंका ने महिलाओं के साथ सुआ नृत्य भी किया। साथ ही प्रदेश की पारंपरिक खेल भंवरा खेलकर भी दिखाया।

प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहा, छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी का भी दौरा है। इसके बाद 25 को राहुल गांधी आएंगे, उनके बाद 28 को खड़गे भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रियंका गांधी के इस दौरे को उचित शर्मा ने महत्वपूर्ण बताया है। शर्मा का कहना है, प्रियंका गांधी महिलाओं का नेतृत्व करतीं हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग आधे से ज्यादा वोटर महिलाएं हैं। यूपी में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था। उसी मंशा के साथ वे छत्तीसगढ़ पहुंची।

उचित शर्मा का कहना है, विधानसभा चुनाव 2018 चुनाव की बात की जाए, तो उस दौरान महिला वोटरों का लगभग 49 फीसदी वोट कांग्रेस के पास थे। वहीं 39 फीसदी वोट भाजपा के पास थे। इन दोनों दलों के बीच लगभग 10 फीसदी का फासला था। इस 10 फीसदी वोटरों को साधे रखने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी का दौरा होता रहेगा, जिससे महिला वोटर को अपने पक्ष में लाया जा सके। इस समय महिला आरक्षण बिल पर पूरे देश में चर्चा चल रही है, ऐसे में प्रियंका गांधी का यह दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 3 करोड़ 3 लाख 80 हजार है। कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 96 लाख 40 हाजर 430 मतदाता है, जो आबादी का लगभग 64.65% है। जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 98 लाख 6 हजार 906 है, जबकि महिला मतदाता 98 लाख 32 हजार 557 है। वही थर्ड जेंडर 767 हैं। यदि रेशियो की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। प्रति हजार पर 1003 महिला मतदाता हैं।

निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के पांच लाख युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। एक अक्टूबर 2023 तक 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 4 ।43 लाख है, जो इस विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। 20 से 29 साल की आयु के युवा मतदाताओं की संख्या 43 लाख 92 हजार है, जो 18 से 19 साल तक के मतदाताओं से पांच लाख से अधिक है। प्रदेश में 30 वर्ष से कम उम्र वाले कुल मतदाताओं की संख्या 48 लाख से अधिक है। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 1 ।97 करोड़ है। वहीं राज्य कुल आबादी 3 करोड़ के करीब है।

22 राइस मिलर्स को नोटिस, नहीं जमा किया चावल

■ 126 केन्द्रों पर छह लाख 64 हजार 56 मीट्रिक टन धान का हुआ उपार्जन

बेमेतरा। बेमेतरा में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में बेमेतरा जिले के 126 उपार्जन केन्द्र के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कुल छह लाख 64 हजार 56 मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी नितिन त्रिवेदी ने बताया कि जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का जिले व अन्य जिले बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, दुर्ग व रायपुर के राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए नौ मार्च 2023 तक संपूर्ण उपार्जित धान का शत प्रतिशत उठाव के विरूद्ध 89 प्रतिशत चावल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में अब तक जमा किया जा चुका है।

वहीं अभी भी कस्टम मिलिंग के तहत करीब 20 प्रतिशत चावल जमा किया जाना बाकी है। इस लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर पीएस एल्मा ने ऐसे 22 राइस मिलर्स जिनके द्वारा धान उठाव के बाद भी चावल जमा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस

जारी किया है। निर्धारित समयावधि तक उठाव किए गए धान के विरूद्ध अनुपातिक चावल जमा नहीं किए जाने पर संबंधित राइस मिलर्स के विरूद्ध चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधनों व राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित से किए गए अनुबंध के शर्तों के तहत आगामी तीन वर्ष कस्टम मिलिंग के लिए ब्लैक लिस्ट सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में धर्मपत्नी के साथ शामिल हुए मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां

अपने निवास परिसर में तीजा पोरा तिहार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम एवं राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं इस त्योहार का उत्सव मनाने मुख्यमंत्री निवास में पहुंची हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल सहित परिवार के लोग उपस्थित हैं। इसके साथ ही संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन भी इस अवसर पर मौजूद हैं।

25 सितंबर को आ सकते हैं अखिलेश यादव रायपुर

रायपुर। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को

देखते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के 25 सितंबर को रायपुर आने की संभावना है, यहां वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आ रहे। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं। उल्लेखनीय हैं कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान व तेलंगाना में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में सपा पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ती आ रही है और सबसे कमजोर छत्तीसगढ़ में है इसलिए सपा अध्यक्ष इस बार छत्तीसगढ़ को मजबूत करने के लिए अपना चुनावी अभियान भी यहां से शुरू करेंगे। सपा ने राज्य बनने के बाद वर्ष 2003 में हुए पहले चुनाव में 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा की 52 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। तब उसे 1.57 प्रतिशत मत मिले थे। वर्ष 2018 के चुनाव में सपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे एक प्रतिशत से भी कम मत मिले।

दम्मानी बंधु अभी जेल में ही रहेंगे

रायपुर। महादेव आनलाइन सट्टा एप के

मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए पेट्रोल पंप और ज्वेलरी कारोबारी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अनिल और सुनील सगे भाई हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अनिल और सुनील को झूठे मामले में फंसाकर बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर पूछताछ करने और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आरोप लगाया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि महादेव आनलाइन सट्टा एप में अनिल और सुनील की संलिप्तता मिली थी। इस समय महादेव एप मामले की जांच चल रही है। जमानत पर रिहा होने पर दोनों जांच को प्रभावित करने के लिए गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया।

गुजराती स्कूल के पदक विजेता खिलाड़ी हुए सम्मानित

रायपुर। 14वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले गुजराती स्कूल के खिलाडियों को गुरुवार को सम्मानित किया गया। एक स्वर्ण समेत पांच पदक जीतने वाले स्कूल के छात्रों व प्रशिक्षक को 25 हजार रुपए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय स्पर्धा में स्कूल की मानसी तांडी ने स्वर्ण पदक जीती थी। इसके अलावा टीसा साहू, लीना यादव, पिंकी गुप्ता और रागिनी यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। पदक विजेता के अलावा राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेने स्कूल के अन्य खिलाड़ी मंजू साहू, मीनाक्षी साहू, मयंक पाल और पुष्पेन्द्र साहू के साथ प्रशिक्षक टिकेश्वरी साहू, मैनेजर झरना यादव और प्रदीप बारीक को गुजराती शिक्षण संघ के अध्यक्ष नारायण भाई पटेल समेत अन्य पदाधिकारियों ने प्रोत्साहन राशि, प्रमाणपत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गुजराती शाला के प्राचार्य अनीस मेमन, प्रथम सहायक प्रवीण गनोदवाले, अंग्रेजी माध्यम शाला के प्राचार्य डॉ. शैलेष शर्मा, प्राथमिक शाला की प्रभारी योगिता टांक समेत छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे।

सूर्यांश मिश्रा का स्क्वैश अंडर 14 में चयन

रायपुर। सूर्यांश मिश्रा का स्कूली स्क्वैश अंडर 14 टीम में चयन हुआ है। 20 से 23 अक्टूबर तक रायपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बूढ़ापारा स्थित स्क्वैश हॉल में रायपुर संभाग की स्क्वैश अंडर 14 अंडर 17 और अंडर 19 की टीम का चयन किया गया जिसमें होलीक्रॉस स्कूल बैरन बाजार रायपुर के कक्षा 6 के छात्र सूर्यांश मिश्रा का चयन अंडर 14 स्क्वैश टीम में हुआ है। सूर्यांश पढ़ाई में भी मेधावी छात्र है।

गुजरात, महाराष्ट्र के 90 विधायकों को ठेके पर सौंपे 90 सीटें : कांग्रेस

भाजपा की परिवर्तन यात्रा में नहीं आ रही भीड़, छत्तीसगढ़ में नीति, नेता और विश्वसनीय के संकट से जूझ रहे हैं भाजपाई

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के परिवर्तन यात्रा को न केवल जनता, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी नकार दिया है। बाहर से बुलाए गए नेताओं के भरोसे निकल गई परिवर्तन यात्रा का भाजपा के ही स्थानीय कार्यकर्ता खुलकर विरोध कर रहे हैं, लोगों की भीड़ कहीं नहीं आ रही है, उल्टे हर जगह इनकी गुटबाजी सामने आ रही है। जमीनी हकीकत यही है कि भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नीति, नीयत, नेता और विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है।

देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों, नड्डा सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीयों के कार्यक्रम भी पूरी तरह से असफल साबित हुए। इनकी कोरी लफ्फाजी और तथ्यहीन आरोपों से भाजपा के झूठा, भ्रम और वादा खिलाफी ही हर बार उजागर हुआ है। 2018 की तरह ही छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भी भाजपाइयों पर भरोसा नहीं कर रही है।

वर्मा ने कहा है कि 2018 में विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी जी 4-4 बार छत्तीसगढ़ आए थे, परिणाम सर्वविदित है। अमित शाह ने 2018 के विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को 65 प्लस का नारा दिया, लेकिन हुआ उल्टा 15 साल के कुशासन के बाद भाजपाई 15 सीट में सिमट गई, आज इनके कुल 13 विधायक ही बचे हैं। कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली थी जो उपचुनाव के बाद अब

71 हो गई है। इतनी बड़ी हार के बाद भी भाजपाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ है, भाजपा के हर बड़े कार्यक्रम के बाद भाजपा का झूठ ही उजागर हुआ है। विगत दिनों साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री से धान खरीदी के बारे में झूठ बुलवाया गया और फिर रायगढ़ की सभा में जी-20 की बैठक को लेकर गलत बयानी की गई। छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है पर बेहद समझदार है, अब इनके जुमलों और झासों में नहीं आने वाली।

दंतेवाड़ा से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री शाह को आना था, नहीं आए, स्मृति ईरानी आई तो वह भी जगदलपुर तक ही, एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकाली और वापस लौट गईं। इससे पहले तथाकथित फर्जी आरोप पत्र जारी करने वाले कार्यक्रम का हश्र भी सबने देखा है। महज़ 1500 की क्षमता वाले ऑडिटोरियम को आधा भरने के लिए भी कार्यक्रम को 2 घंटे विलंब करना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह इंतज़ार करते रहे, फिर भी लोग नहीं आए। सरायपाली की सभा को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही असफल कर दिया।

राजिम, केशकाल, बालोद और डौंडीलोहारा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिवर्तन यात्रा का जगह-जगह उन्हीं के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। प्रभारी, स्टार प्रचारक और सहयोगी तो चुनाव के दौरान पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र को गुजरात महाराष्ट्र के 90 विधायकों को ठेके पर सौंप दिया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने पर कांग्रेस का कटाक्ष

भीड़ न होने की वजह से शाह का दौरा रद्द : अमरजीत भगत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। अमित शाह का दौरा रद्द होने को लेकर उन्होंने कहा कि शाह की सभा में लोगों की भीड़ कम होती है। यही कारण है कि केन्द्रीय गृहमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने अपने पिछले दौरे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की जमकर क्लास ली थी।

दरअसल, शुक्रवार को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया है। शाह रायपुर में एक बड़ी बैठक में शामिल होने वाले थे। शाह का दौरा रद्द होने को लेकर बीजेपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली के कार्यक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री व्यस्त हैं। इसलिए उनका दौरा रद्द हुआ है। जिस पर कांग्रेस की तरफ से अमरजीत भगत ने निशाना साधा है।

मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में उमड़ी भीड़ को लेकर

उन्होंने कहा कि, भाजपा अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। खुद को खुश करने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्रा में भीड़ होने की बात कह रही है। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जब यहां का दौरा किया था। तो उसमें भीड़ नहीं जुटी। यही कारण है कि यहां के बीजेपी के नेताओं को अमित शाह ने डांट लगाई है। उन्होंने सिर्फ इन नेताओं की पिटाई नहीं की, बाकी सबकी पूरी क्लास ली है। बीजेपी के यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भीड़ नहीं आ रही है, इसलिए सभी लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। अमरजीत भगत ने कहा भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं जुट रही है। इसे लेकर उनके वरिष्ठ नेताओं में काफी नाराजगी है। इस मुद्दे पर यहां तक कि अमित शाह ने यहां के भाजपा नेताओं की जमकर क्लास ली है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का शुक्रवार छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया है। इसके पहले भी 12 सितंबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले थे, जहां वे दंतेवाड़ा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू करने वाले थे। उस दौरान भी अचानक से अमित शाह का दौरा रद्द हो गया था। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने एक बार फिर अमित शाह के दौरे के रद्द होने पर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी की भीड़ न जुटने के कारण दौरा रद्द होने की बात कही है।

6 माह में 15 लाख से भी अधिक यात्रियों ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से किया टिकटों की बुकिंग

■ **मोबाइल ऐप से जनरल टिकट की खरीदी में हो रही है लगातार बढ़ोत्तरी**

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्री सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस श्रृंखला में ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा के बाद मोबाइल से ऐप द्वारा जनरल टिकट खरीदने की सुविधा यात्रियों को दी गई है। इस सुविधा से यात्रियों को स्टेशन पर आकार टिकट काउंटर से लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदने की बाध्यता समाप्त हो गई है। इस यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप को यात्रियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एवं दिनों-दिन इस सुविधा के उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

यात्रियों को टिकट काउण्टरों में लगने वाली लाइनों से निजात दिलाने, शीघ्र टिकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घर बैठे यात्रा टिकट बुकिंग के साथ साथ सीजन टिकट(एमएसटी) जारी व नवीनीकरण कराने हेतु यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। यात्री अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे आसानी के साथ त्वरित अनारक्षित टिकट बुकिंग तथा सीजन टिकट(एमएसटी) जारी व नवीनीकरण कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म टिकट भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि स्टेशन से दूर रहने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके दायरे को बढ़ाकर 25 किमी भी कर दिया गया है, अर्थात

यात्रीगण स्टेशन से 25 किमी की दूरी से भी इस ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग तथा सीजन टिकट(एमएसटी) जारी व नवीनीकरण कर सकते हैं।

इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक कुल आरक्षित टिकटों की बुकिंग में 80 प्रतिशत से भी अधिक मोबाइल टिकटिंग से बुक किए गए। इसी प्रकार इसी समान अवधि में लगभग 15 लाख से भी अधिक रेल यात्रियों ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के द्वारा अनारक्षित टिकट की खरीदी कर यात्रा की। रेलवे प्रशासन यात्रियों से आग्रह करता है कि त्वरित घर बैठे आसानी से इस ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग तथा सीजन टिकट(एमएसटी) जारी व नवीनीकरण कराने की इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठावें।

छत्तीसगढ़ आकर प्रियंका प्रदेश के किसानों और माता-बहनों से झूठ बोलकर चली गईं : भाजपा

■ **उप्र के किसान को अपने धान की कीमत पता है, प्रियंका तो यह बताएँ कि छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या कीमत मिलेगी?**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा छत्तीसगढ़ आईं और झूठ परोस कर चली गईं। यहां आकर प्रदेश के किसान भाइयों और माता-बहनों से झूठ बोलकर चली गईं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आकर धान खरीदने का श्रेय लेते हैं, मैं यूपी से आती हूं और उनसे पूछना चाहती हूं कि यदि मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है, तो उत्तरप्रदेश के किसान अपना धान 1200 से 1400 रु में क्यों बेच रहे हैं? वहां पर तो बीजेपी की सरकार है।% श्री शर्मा ने कहा कि प्रियंका वाड्रा को मालूम ही नहीं है कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार किसानों से कितनी कीमत पर धान खरीद रही है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने प्रियंका वाड्रा के आरोपों के जवाब में कहा कि योगी सरकार ने उप्र के किसानों के लिए धान खरीदी की नई नीति तय कर दी है। योगी सरकार ने प्रति क्विंटल 143 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब वहां के किसान भाइयों को बढ़ी हुई दर पर कामन धान 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। वहां के किसान

भाइयों को मालूम है कि उनके धान की कितनी कीमत मिलेगी? श्री शर्मा ने कहा कि प्रियंका वाड्रा छत्तीसगढ़ के किसानों को बताएँ कि उनकी भूपेश बघेल की सरकार किसानों से कितनी कीमत पर धान खरीदेगी, क्योंकि उनके कोई मंत्री 26 सौ रुपए बोल रहा है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष 35 सौ से 4 हजार रुपए में खरीदने की बात कह रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के किसान दुविधा में है कि उनके उपज की सही कीमत क्या है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि धान खरीदी में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, जबकि उन्हीं के मंत्री रवींद्र चौबे कहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के धान की लगातार कीमत बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर अर्थिक सहयोग नहीं देने की बात कहते हैं तो उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव केंद्र सरकार से भरपूर आर्थिक मदद मिलने की बात सार्वजनिक मंच से स्वीकार करते हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री बघेल और प्रियंका वाड्रा को चुनौती देते हुए कहा कि धान खरीदी पर वे जो झूठ की दुकान खोलकर बैठे हैं, उसकी सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने केंद्रीय पूल के चावल का कोटा इतना बढ़ा दिया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी संभव है। अब तक मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सारी खरीदी वे ही करते हैं। अब राज्य के नुकसान की बात कर रहे हैं। सत्य यह है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए कोटा बढ़ाया है। राज्य के बजट में तो धान खरीदी के लिए कोई विशेष व्यवस्था ही नहीं है। कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के बारे में झूठ बोलने का सबसे बड़ा प्रमाण तो राज्य का बजट है। अगर राज्य अपनी योजना से धान खरीदेगी तो उसके बजट में पैसे का प्रावधान करना पड़ेगा। धान खरीदी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग करता है, 2022-23 के लिए इस विभाग का कुल बजट 5158 करोड़ रुपए है, ऐसे में धान खरीदने के लिए 21 हजार 828 करोड़ रुपए कहां से आयेंगे? यहां तक कि तीन अनुपूरक बजट को मिलाकर भी इतनी बड़ी राशि नहीं होती।

राज्य स्तरीय छत्तीसगढिया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 तक रायपुर में

रायपुर। राज्य स्तरीय छत्तीसगढिया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितम्बर तक रायपुर में होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को राज्य स्तरीय छत्तीसगढिया ओलंपिक 2023-24 में जिले के प्रतिभागी, दल को सम्मिलित कराने के लिए दिशा-निर्देश दिए है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढिया ओलंपिक का आयोजन के संबंध में 24 सितम्बर को शाम 7 बजे सभी जिलों के दल मैनेजर एवं खेल अधिकारियों की बैठक सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है। बैठक में विधावार प्रतिभागी, मैनेजरों की सूची के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय से जिला कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढिया ओलंपिक 2023-24 के आयोजन के संबंध में पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके है। राज्य स्तर छत्तीसगढिया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितम्बर तक रायपुर में आयोजित है, जिसमें भागीदारी करने वाले प्रतिभागी और दलों को भेजनें के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राज्य स्तर पर आने वाले प्रतिभागी दलों के साथ संबंधित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक-एक डिप्टी कलेक्टर तथा उप पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी लगाई जाए। जिलों से आने वाले महिला प्रतिभागियों के साथ अनिवार्य रूप से महिला कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। राज्य स्तर पर शामिल होने वाले संभाग स्तरीय प्रत्येक जिले के प्रतिभागी को पहचान पत्र प्रदाय किए जाने हेतु प्रारूप संभाग द्वारा सभी जिलों के खेल अधिकारियों का उपलब्ध करा दी गई है। अतः यह सुनिश्चित करें कि जिले से आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी निर्धारित प्रारूप में जिला खेल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील सहित पहचान पत्र के साथ ही यात्रा करें। जिले के दल 24 सितम्बर को सायं 6 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दें। जिलों के दल मैनेजर प्रत्येक विधावार नियुक्त प्रभारी से समन्वय कर, प्रतिभागी, दल को सुव्यवस्थित रूप से प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं तथा विधावार निर्धारित प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर समय पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

शराबबंदी के वादे पर मातृ-शक्ति से धोखाधड़ी, अब इस शराब का नशा चढ़ गया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और पूर्व संसदीय सचिव चम्पादेवी पावले ने कांग्रेस सरकार के मंत्री कवासी लखमा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि मंत्री लखमा अपने बयान से जिस तरह छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इसका खामियाजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा नेत्रियों ने कहा कि गंगाजल की सौगंध लेकर पूर्ण शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आ गई। शराबबंदी के वादे पर प्रदेश की मातृ-शक्ति से धोखाधड़ी करने वाली कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार को अब इस शराब का नशा चढ़ गया है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती वर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राजपूत व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती पावले ने कहा कि मंत्री लखमा जो कह रहे हैं कि वह जहाँ जाते हैं वहाँ शराब दुकान खोलने की मांग आती है, तो क्या लखमा यह कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता शराबी है। प्रदेश

की भूपेश सरकार की शराब के कारण हजारों बहनों का सुहाग उजड़ गया, घर बिक गए, परिवार बिखर गए और प्रदेश सरकार उनके घर तक शराब पहुँचाने में लगी है। महिला नेत्रियों ने आगाह किया कि प्रदेश सरकार यह याद रखे कि छत्तीसगढ़ की बहनों का अभिशाप कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने बड़बोलेपन से बाज आ जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संसद-विधानमंडलों में 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पारित कराते हैं और दूसरी तरफ प्रदेश की कांग्रेस सरकार शराब घर-घर पहुँचाकर प्रदेश की महिलाओं का मखौल उड़ाकर अपमान कर रही है। मातृ-शक्ति के इस अपमान की कीमत चुकाने के लिए कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार तैयार हो जाए।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती वर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राजपूत व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती पावले ने कहा कि राजधानी रायपुर में एडिशनल एसपी कार्यालय के पास जयस्तंभ चौक में नाबालिग किशोरी से गैंगरेप हो जाता है। इससे अधिक दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है? यह घटना कोई अचानक नहीं हुई है। लगातार प्रदेशभर में अनाचार की घटनाएँ हो रही हैं। रायपुर शहर में खुलेआम एक व्यक्ति गंडासा हाथ में लिए लड़की को लेकर घूमता है और सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहती है। जिस प्रकार से घटनाएँ हो रही हैं, अब तो सिर्फ मुख्यमंत्री निवास ही बचा है।

कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग-बलौदाबाजार

Office Phone and Fax No.:- 07727-296695 Email ID :- ee-res.abhanpur@nic.in

// मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना क्र.- 55/

क्रमांक/5372/ निविदा/ग्रा.यां.से./ 2023-24 बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2023

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रथम बार मैन्युअल निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र	कार्य का विवरण	कार्यों की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
1.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (ब्राम्हण पारा) सिमगा विद्युतीकरण सहित, भवन उन्नयन कार्य (देवांगन पारा) सिमगा विद्युतीकरण सहित, भवन उन्नयन कार्य (साहू पारा) सिमगा, रंगमंच निर्माण कार्य (विश्वकर्मा पारा) सिमगा।	19.04
2.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (निषाद पारा) सिमगा विद्युतीकरण सहित, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (शिव पारा) सिमगा विद्युतीकरण सहित वि.खं. सिमगा।	14.73

2/ निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट-2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट-2.13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट http://cg.nic.in/resworks अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 21.09.2023 से देखी जा सकती है एवं डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 03.10.2023 तक है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग बलौदाबाजार

जी-05613/3

महिला आरक्षण बिल से किसे फायदा

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

केंद्र सरकार ने जब संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की तो दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ गया और कयास के बादल मंडराने लगे कि अचानक विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। महिला आरक्षण विधेयक लाने की घोषणा के बाद यह साफ हुआ कि सरकार की मंशा 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महिला वोटरों में पैठ बनाने की कोशिश है। लेकिन यह बिल लागू होगा 2029 से। अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि इसे 2029 तक क्यों टाला जा रहा है। उसकी मांग है कि 2024 लोकसभा चुनाव से ही इसे लागू होना चाहिए। वैसे राजनीति अपनी जगह, लेकिन 27 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण विधेयक का संसद से पारित हो जाना वाकई ऐतिहासिक है। संयोग देखिए, 27 साल से धूल फांकते इस बिल की किस्मत नई संसद में खुली है। इस बिल के कानून बन जाने और लागू होने के बाद संसद के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव दिखेंगे। लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इस बिल में आरक्षण की अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दलित और आदिवासियों के लिए जितनी सीटें लोकसभा और विधानसभा के लिए आरक्षित हैं, उनमें से 33त्न इस समुदाय की महिलाओं के लिए निर्धारित हो जाएंगी। ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि ओबीसी आरक्षण की मांग के चलते यह बिल इतने समय लटका रहा। इस बिल के तहत महिला आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद इसे जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा। दिलचस्प है कि आजादी के आंदोलन में अच्छी भागीदारी के बावजूद आजादी के बाद महिलाओं को राजनीति में ठीकठाक नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। आज भी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी करीब 15 फीसदी और राज्यसभा में 13 फीसदी ही है। लोकसभा में 15 फीसदी की भागीदारी भी पहली बार 2019 के चुनाव में ही हो पाई। 1977 में जेपी आंदोलन के बावजूद महिला का प्रतिनिधित्व सबसे खराब स्तर पर था, महज 3.5 फीसदी। ऐसे में महिला आरक्षण बिल की अहमियत जगजाहिर है। लेकिन इसकी अब तक की यात्रा भी बड़ी दिलचस्प रही। इसे 1996 में तैयार किया गया था, लेकिन यह शुरू से ही विवादों में फंसा रहा। पहली दफा विरोधी नेताओं ने इसे पेश ही नहीं करने दिया। उसके बाद 1998 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने कोशिश की तो उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई, जिनमें उनकी सरकार के मंत्री शरद यादव प्रमुख थे। उसी साल बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इसे पेश करने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसे सदन में फाड़ डाला। कानून मंत्री थंबी दोरई की कमीज भी फाड़ दी गई। 2000 में कानून मंत्री रामजेठमलानी ने बिल तो पेश कर दिया, लेकिन पास नहीं करवा पाए। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने महिला आरक्षण पर सहमति के लिए 3 मार्च, 2002 को सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में सहमति नहीं बन पाई क्योंकि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी इसमें पिछड़ों के लिए कोटे की मांग पर अड़ी रही। यूपीए सरकार ने भी कोशिश की, पर वह भी इसे राज्यसभा में ही पास करा सकी। अब मोदी सरकार इसे लेकर आई तो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सोनिया गांधी ने इस बिल का समर्थन किया और कहा कि यह बिल राजीव गांधी का सपना था। कांग्रेस की मांग है कि इस बिल को तत्काल अमल में लाया जाए। इन सबके बीच बीजेपी इस विधेयक को मोदी सरकार की प्रथमिकता से जोड़ रही है। उसका कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है, इसका महिला सशक्तीकरण पर खासा जोर रहा है। बात गलत भी नहीं। पीएम मोदी ने न सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। करीब 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाया गया ताकि महिलाओं को खुले में शौच ना करना पड़े। फ्री गैस सिलिंडर देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना, जनधन योजना के तहत 50 करोड़ लोगों का बैंकों में खाता खुलवाना- इन तमाम योजनाओं के जरिए महिला को ताकत देने की कोशिश हुई। नौकरीपेशा महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 12 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया। 3.18 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते खुलवाए गए। उनकी सेहत के लिए एक रुपये की दर से 27 करोड़ सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए। घरेलू महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन जैसी योजना शुरू की गई ताकि घरेलू महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

पेरियार की विचारधारा पर कांग्रेस ?

अजय सेतिया

16 सितंबर को हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्यसमिति ने सनातन के मुद्दे पर बयानबाजी से बचने का फैसला किया था। इसी बैठक में जाति आधारित जनगणना की मांग भी रखी गई। वैसे यूपीए शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई थी, लेकिन समाज में वैमनस्य पैदा न हो इसलिए आंकड़े जगजाहिर नहीं किए गए थे।

अब राहुल गांधी ने लोकसभा में जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार की ओर से करवाई गई जाति आधारित आंकड़ों को जगजाहिर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो वह खुद आंकड़े जगजाहिर कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि वे सरकारी दस्तावेज उनके पास हैं, जो सरकारी कार्यालय से चोरी किए गए हैं। यूपीए सरकार ने वे आंकड़े अपने शासनकाल में इसलिए जारी नहीं किए थे, क्योंकि उन्हें समाज में वैमनस्य पैदा होने का डर था। लेकिन अब राहुल गांधी उन आंकड़ों को इसलिए जारी करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वे हिन्दुओं में जाति आधारित वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं।

इंडी एलायंस की मुम्बई बैठक में जाति आधारित जनगणना पर गहरे मतभेद थे। यह मांग राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने की थी। इन्हीं दलों के दबाव में तत्कालीन यूपीए सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई थी। यह जाति आधारित राजनीति 1990 से चल रही थी, जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया था। हिन्दू समाज में अगड़ों और पिछड़ों में जबर्दस्त वैमनस्य की स्थिति पैदा हो गई थी, जो लगभग 25 साल तक चली। 2014 में सनातन धर्म की विभिन्न जातियां अपने मतभेद भुला कर हिंदुत्व के झंडे तले एकजुट हो गईं, तब से भाजपा दो बार स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीत चुकी है। इसलिए कांग्रेस को अब लगता है कि जाति आधारित राजनीति बहुत जरूरी है। कांग्रेस के इतिहास में शायद यह पहला मौक़ा है, जब कांग्रेस ने खुलेआम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अगड़ों के खिलाफ भड़का कर चुनावी राजनीति करने का फैसला किया है। वरना कांग्रेस का इतिहास ऊंची जातियों खासकर ब्राह्मण नेतृत्व का ही रहा है। 1925 में तमिलनाडू के रामास्वामी पेरियार ने कांग्रेस को ब्राह्मणवादी पार्टी कहते हुए ही कांग्रेस छोड़ी थी। पेरियार सनातन धर्म का भी इसलिए विरोध करते थे, क्योंकि सनातन धर्म में जाति आधारित भेदभाव और छूआछूत थी।

वैसे सनातन कोई संप्रदाय नहीं है, सनातन का अर्थ है, जो सत्य है, जिसका न आदि है, न अंत है, जो सत्य है, वही सनातन है। सनातन एक जीवन पद्धति है, जो हजारों सालों से इस धरती पर रहने वाले लोगों का धर्म था। समय के साथ सनातन को संप्रदाय के रूप में लिया जाने लगा। तुर्क और ईरानी सिन्धु घाटी पार करके भारत आए, तो उन्होंने भारत के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। धीरे धीरे सनातन से ज्यादा हिन्दू प्रचलित हो गया। फिर हिन्दुओं में जातिवाद शुरू हुआ, फिर छुआछूत शुरू हो गया।

हिन्दुओं में आई इन बुराईयों के खिलाफ कई सुधारवादी आन्दोलन भी चले। अनेक समाज सुधारक हुए, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और छूआछूत के खिलाफ आन्दोलन चलाए। हिन्दुओं ने अपनी बुराईयों को दूर करने के लिए बनाए गए कानूनों को स्वीकार किया। लेकिन पेरियार का जातिवाद के खिलाफ शुरू हुआ आन्दोलन धीरे धीरे हिन्दू विरोधी और हिन्दी विरोधी बन गया। उनका कहना था कि उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने दक्षिण में आकर जातिवाद फैलाया, वरना द्रविड़ संस्कृति में जातिवाद नहीं था।

कांग्रेस छोड़ने के बाद पेरियार ने स्वाभिमान आन्दोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी सत्ता को समाप्त करके जाति, धर्म और भगवान से रहित एक तर्क आधारित समाज का निर्माण करना था। उनका कहना था कि द्रविड़ सनातनी नहीं हैं, द्रविड़ों की अपनी संस्कृति और भाषा है। बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी के साथ मिलकर आन्दोलन को आगे बढ़ाया।

जस्टिस पार्टी का जन्म भी 1915-16 में ऊंची जातियों के खिलाफ हुआ था। जस्टिस पार्टी में मद्रास, आंध्र और केरल की मझौली जातियां थीं, जो अंग्रेजों की ओर से ब्राह्मणों को ज्यादा अहमियत दिए जाने के खिलाफ थीं। सनातन विरोध के मूल में अंगरेजी शासनकाल में ब्राह्मणों को मिली तव्वजो और कांग्रेस में ब्राह्मणों का बोलबाला था।

आज़ादी के बाद पेरियार के करीबी सी. एन. अन्नादुरैई ने डीएमके पार्टी का गठन किया। कांग्रेस के ब्राह्मणवादी नेतृत्व के खिलाफ ही डीएमके का गठन हुआ था और वह शुरू से ही हिन्दुओं और हिन्दी के खिलाफ थी। इसलिए करुणानिधि के पोते और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ बोल कर कुछ नई बात नहीं कही, लेकिन इस समय यह बात कहने का कोई मतलब नहीं था।

बात गंभीर तब हो गई जब डीएमके सरकार के ही एक अन्य मंत्री ने कहा कि इंडी एलायंस का गठन ही सनातन विरोध के आधार पर हुआ है। अगर यह सही नहीं था तो गठबंधन की तरफ से खंडन किया जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने ही सनातन पर आए बयान का विरोध किया। कांग्रेस ने अपनी हैदराबाद कार्यसमिति में सनातन के मुद्दे पर स्पष्ट स्टैंड लेने की बजाए, इस मुद्दे से बचने की बात कही।

दूसरी बात यह हुई कि कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग उठा दी है। लोकसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर आए बिल के समर्थन में बोलते हुए राहुल गांधी ने बहुत ही उत्तेजित होकर जातीय जनगणना की मांग रख दी। यह मांग इसलिए रखी गई है, ताकि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण दिया जाए।

यह वही कांग्रेस है, जिसने पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सिफारिश करने वाली मंडल आयोग की सिफारिशें दस साल तक दबाए रखी थीं। अन्य पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक और आर्थित्क स्थिति का आकलन करने के लिए मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता सरकार ने किया था। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने दस साल तक दबाए रखी थीं। जब दूसरी बार 1989 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब जाकर 1990 में आरक्षण की सिफारिशे लागू हुईं।

अब जाति आधारित जनगणना की मांग करके कांग्रेस ओबीसी का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। यह जाति आधारित जनगणना की मांग उनके खिलाफ है, जिन्हें योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। कांग्रेस के इस नए आन्दोलन का मतलब योग्यता के आधार पर मिलने वाली नौकरियों को कम करना है। पेरियार के संगठन और जस्टिस पार्टी का आन्दोलन भी ब्राह्मणों और ठाकुरों के खिलाफ था, जिन्हें शिक्षित होने के कारण ब्रिटिश राज में ज्यादा नौकरियां मिल रहीं थीं।

पेरियार सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन उनकी विचारधारा नफरत और वैमनस्य की विचारधारा थी। सामाजिक न्याय के लिए संविधान में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण है, जबकि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण है। अगर जाति आधारित जनगणना करके ओबीसी और अन्य जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाता है, और सुप्रीमकोर्ट उसे इजाजत दे देता है, तो योग्यता के आधार पर मिल रही 40 प्रतिशत नौकरियां घट जाएंगी।

फिलहाल सुप्रीमकोर्ट ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगाई हुई है, इसलिए इन जातियों को इससे ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता। मोदी सरकार ने आर्थिक स्थिति के आधार पर सवर्ण जातियों के कम आय वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण का क़ानून पास किया है, जिसे सुप्रीमकोर्ट की सहमति मिल चुकी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-12)

गतांक से आगे...

आदान (ग्रहण करना), गमन (गतिशील होना), विसर्ग (त्याग करना), आनन्द, हान (त्या'य), उपेक्षा- बुद्धि एवं अनङ्ग- कुसुम आदि आठ शक्तियाँ हैं। अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, अश्विनी, गान्धारी, पूषा, शखिनी, सरस्वती, इड़ा, पिङ्गला, सुपुन्ना आदि चौदह नाड़ियाँ सर्वसंक्षोभिणी आदि चतुर्दशार देवता है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनञ्जय- ये दस प्राण सर्वसिद्धिप्रदा आदि देवियाँ बाह्य दशार देवता हैं।

इन दस वायुओं के सम्पर्क एवं उपाधि भेद से रेचक, पूरक, शोषक, दाहक, प्लावक-ये अमृतस्वरूप प्राण मुख्यत: पाँच प्रकार के हैं। मानवों के मोहक एवं दाहक होते हुए चबाये जाने वाले, चाटे जाने वाले, चूसे जाने वाले तथा पिये जाने वाले इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। ये दस अग्नि की कलास्वरूप वायु ही सर्वज्ञत्व आदि अन्त: दशार देवता हैं। जाड़ा, गर्मी, सुख, दु:ख, इच्छा, सत्त्व, रज, तम ही वशिनी आदि आठ शक्तियाँ हैं।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध आदि पञ्च तन्मात्राएँ ही पाँच पुष्पबाण हैं तथा मन ही ईख का बना हुआ धनुष है अर्थात् मन के द्वारा ये रूपादि पञ्चबाण बाहर फेंके जाते हैं। वश में होना ही बाण है, राग (प्रेम) ही पाश (बन्धन) है और द्वेष ही अंकुश है। अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी तथा भगमालिनी आदि आन्तरिक त्रिकोण के अग्रभाग में स्थित देवता हैं।

पन्द्रह तिथियों के रूप से काल के परिणाम का अवलोकन करने वाले पन्द्रह नित्य श्रद्धानुरूप अधिदेवता हैं। उन (वज्रेश्वरी तथा भगमालिनी) में आद्याप्रधान कामेश्वरी जो कि सत, चित् आनन्दघन स्वरूपा हैं एवं परिपूर्ण (ब्रह्म) और आत्मा की ऐक्य रूपा देवता हैं। [यहाँ श्री यन्त्र लेखन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बिन्दु, त्रिकोण, अष्टार, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल पद्म, षोडशदलपद्म और चतुरस्त्र आदि इसके पारिभाषिक शब्द हैं, जिनके द्वारा श्रीयन्त्र लिखा जाता है।]

सलिल अर्थात् गुरु मन्त्रात्मक देवों का एकीकरण रूप सत् तत्त्व ही कर्तृतव्य है और एकीकरण रूप न करना ही अकर्तृतव्य है। भावना योग ही इसका उपचार (पूजा) है। अस्ति (ब्रह्म है) - नास्ति (ब्रह्म नहीं है) की कर्तृतव्यता (निरन्तर अनुसन्धान करना) उपचार है।

क्रमश: ...

रामधारी सिंह दिनकर

कृष्ण प्रताप सिंह

बिहार के बेगूसराय जिले में गंगा के तटवर्ती सिमरिया गांव में, 1908 में 23 सितंबर को माता मनरूपा देवी की कोख से जन्मे रामधारी सिंह 'दिनकर' आम तौर पर अपनी राष्ट्रीयता प्रधान और वीर रस से ओतप्रोत कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अपने वक्त में उन्हें जो कोई भी अपनी धारणाओं के प्रतिकूल लगा, उसकी आलोचना में या उसे खरी-खरी सुनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्ष 1962 के युद्ध में चीन से पराजय के बाद उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा। लेकिन उनकी साहित्य सेवा को दूसरे पहलू से देखें, तो वह 'उर्वशी' जैसी प्रेम व सौंदर्य की अद्भुत अनुभूतियों से भरी कृति भी दे गये हैं।

खांचे में वैसे उनका वह गद्य साहित्य भी नहीं बैठता, जो न परिमाण के मामले में कम है, न ही गुणवत्ता के। यह और बात है कि फिर भी वह उनके 'राष्ट्रकवि' होने के साइड-इफेक्ट झेलने को अभिशप्त हैं। बहरहाल, किसी खांचे या सांचे में फिट न होने के ही कारण पराधीनता के दौरान उन्हें 'विद्रोही कवि' और स्वतंत्रता के बाद 'राष्ट्रकवि' कहा गया, वहीं उनकी कविताओं में किये गये कई आह्वानों ने कुछ ऐसी जगह बनायी कि उनके लिए जनकवि का आसन भी सुरक्षित हो गया। उनकी कविताओं के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने तब थे।

उनका पहला कविता संग्रह 'बारदोली विजय संदेश', और संभवत: प्रणभंग भी, उनके सब-रजिस्ट्रार बनने से पहले ही छप चुका था, और उनकी ख्याति फैलने लगी थी। लेकिन 1935 में 'कितनी मणियां लुट गयीं? मिटा कितना मेरा वैभव अशेष?' पूछती और 'तू मौन त्याग, कर सिंहनाद, रे तापी!' का आह्वान करती देशभक्ति की कविताओं से भरी 'रेणुका' का प्रकाशन हुआ, तो अपराधबोध से पीड़ित गोरी सत्ता को लगा, कि उसमें सब कुछ उसके ही खिलाफ है।

उसने इसे मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं के तौर पर लेकर उन्हें मजा चखाने का फैसला किया। पहले उसने 'रेणुका' का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, ताकि उसे ठीक से समझ कैफियत तलब की जा सके। फिर फाइल तैयार की गयी और मुजफ्फरपुर के अंग्रेज डीएम से कहा गया कि वह दिनकर को चेतावनी दें। डीएम ने पूछा कि उन्होंने सरकार विरोधी कविताएं क्यों लिखीं, और प्रकाशन से पहले अनुमति क्यों नहीं मांगी, दिनकर का उत्तर था, 'रेणुका की कविताएं सरकार विरोधी नहीं, मात्र देशभक्तिपूर्ण हैं। कृपया बतायें कि क्या देशभक्ति भी अपराध है? डीएम कैसे कहता कि देशभक्ति अपराध है? इसलिए बात चेतावनी देने तक ही रह गयी। यह तो शुरुआत थी। 'हुंकार' प्रकाशित होते ही उनका मुंगेर के डीएम की चेतावनी से भी साबका पड़ गया। गनीमत थी कि वह भारतीय था। उसने कहा, 'रोज-रोज बखेड़ा मत खड़ा किया कीजिए। चार साल में उन्हें 22 स्थानांतरण झेलने पड़े। पर उनकी विद्रोही कलम न कहीं रुकी, न झुकी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कह गये हैं कि वह हिंदी तो हिंदी, अहिंदी भाषियों में भी अपने समय के सबसे लोकप्रिय कवि थे। उन्हें 1959 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया, और 'संस्कृति के चार अध्याय' के लिए इसी साल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वर्ष 1972 में उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।

काबुल में भारत की रणनीति यानी एक तीर से कई निशाने

महेंद्र वेद

हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान में अपना स्थायी राजदूत तैनात किया है। चीन वह पहला देश है, जिसने तालिबानी शासन स्थापित होने के बाद ऐसा किया है। इसके विपरीत, भारत लो-प्रोफाइल कूटनीति के जरिये तालिबान शासित काबुल में अपनी मौजूदगी स्थापित करने की उम्मीद रखता है, ताकि मानवीय सहायता के माध्यम से अफगानी लोगों के बीच सद्भावना बरकरार रखी जा सके। भारत द्वारा फूंक-फूंककर कदम उठाने का अघोषित मतलब यह है कि एक तरफ जहां अफगानिस्तान में सक्रिय भारतीय हितों के लिए हानिकारक विभिन्न आतंकवादी गुटों पर नजर रखी जा सके, वहीं चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके, जिनके हित पूरी तरह न सही, पर काफी हद तक मिलते हैं।

गोवा में इसी साल हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की थी कि हमारी तात्कालिक प्राथमिकता में मानवीय सहायता प्रदान करना, एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार सुनिश्चित करना, मादक पदार्थों की तस्करी एवं आतंकवाद से मुकाबला करना तथा महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना है। आम अफगानी लोगों के बीच सद्भावना बरकरार रखते हुए भारत ने तालिबान नेतृत्व के एक वर्गे, जैसे कि तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई के साथ, जिन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया, संपर्क बनाए रखा है। गौरतलब है कि तालिबान शासन का जुड़ाव हक्कानी परिवार से है, जिसने अतीत में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए नई दिल्ली

सावधान है कि उसके संबंधों को तालिबान के कूटनीतिक आलिंगन या विरोधी शासन मॉडल के समर्थन में न देखा जाए। बाकी दुनिया की तरह भारत भी तालिबानी शासन को मान्यता नहीं देता है। बिना किसी चुनौती के सत्ता में आए तालिबान से यह उम्मीद नहीं है कि वे विश्व समुदाय की मांग के अनुरूप अपनी महिलाओं और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। अनिवार्य रूप से यह अफगानिस्तान का घरेलू मामला है, लेकिन इस मामले में वैश्विक दबाव काफी हद तक अप्रभावी रहा है। इसलिए अफगानिस्तान के आतंकवाद का केंद्र बनने की चिंता स्वाभाविक एवं गंभीर है।

महिलाओं के खिलाफ तालिबान के धर्मयुद्ध का ताजा खुलासा पिछले महीने तब हुआ, जब दुबई में एक विश्वविद्यालय में समायोजित होने की उम्मीद करने वाले कम से कम 60 संभावित विद्वानों को काबुल हवाई अड्डे से निकाल दिया गया था। इसके बाद इसी तरह की कई घटनाएं हुईं, जो लड़कियों के माध्यमिक या उच्च शिक्षा के अधिकारों को छीनने से लेकर सहायता एजेंसियों में काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध और ब्यूटी पार्लरों पर प्रतिबंध तक फैली हुई है। दोहा वार्ता के दौरान अफगानिस्तान के वार्ताकारों ने संकेत दिया था कि तालिबान 2.0 पाकिस्तान और सऊदी समर्थित अपने पुराने अवतार से अलग होंगे। लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने के लिए उत्सुक अमेरिकियों को बेवकूफ बनाया। पिछले महीने, बामियान में बंद-ए-अमीर राष्ट्रीय उद्यान को महिलाओं के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। असल में तालिबान महिलाओं को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया है कि महिलाओं के लिए दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना जरूरी नहीं है। असहाय दुनिया को यह लग रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी शक्तियों की वर्चस्व की होड़ से अलग कुछ समझदार लोगों के समक्ष यह साफ है कि महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह विकसित और अविकसित सहित सभी समाजों में अलग-अलग स्तर तक व्याप्त हैं। यह रुककर इंतजार करने का वक्त है। सद्दाम हुसैन के इराक में परमाणु शस्त्रागार की खोज से पहले 2001 में तत्कालीन अमेरिकी प्रथम महिला, लौरा बुश ने अफगान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को एक मुद्दा बनाया था, जो अफगानिस्तान पर हमले का एक बहाना बना। कुछ अमेरिकी पत्रकारों ने माना है कि सोवियत समर्थित शासन के दौरान शहरी अफगानिस्तान में महिलाओं को अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए सबसे कम पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कम्युनिस्ट शासित अफगानिस्तान में एक महिला मंत्री अनाहिता रातेब्जाद थीं, जो अफगान संसद के लिए चुनी गई पहली महिलाओं में से एक थीं और 1980 से 1986 तक मुल्क की उप प्रमुख रहीं। वर्ष 1985 में काबुल विश्वविद्यालय में 7,000 छात्रों में से 65 प्रतिशत महिलाएं थीं, जो पिछले समय में या अमेरिका/नाटो की मौजूदगी के दौरान अकल्पनीय थी, जब अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित अफगान मुजाहिदीन ने अधिकांश स्वतंत्रता खत्म कर दी और लड़कियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का गला काट दिया। अब तालिबान सरकार की नीतियों के कारण अफगानिस्तान उन कुछ देशों में से एक है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा आत्महत्या करती हैं। किसी भी देश ने औपचारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, यहां तक कि तालिबान के पुराने अवतार के प्रायोजक-पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी नहीं। काबुल के साथ संबंध रखते हुए भारत अभी तटस्थ है, जबकि पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, तुर्किये, कजाकिस्तान और कुछ अरब एवं अफ्रीकी देशों में अफगान दूतावास तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों के अधीन कार्य कर रहे हैं। चर्चा है कि अफगानिस्तान संभवत: मानवाधिकारों के उल्लंघन से बेपरवाह चीनी संस्थाओं को अपनी धरती के नीचे दबे दुर्लभ खनिजों के दोहन की अनुमति देकर मुनाफा कमा रहा है। तालिबान इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि चीन तांबे का पता लगाकर उसका खनन करे, जिसका उसके पास विशाल भंडार है। इस तरह की गतिविधियों से अफगानिस्तान को स्पष्ट रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे आकर्षक उपज, अफीम, हेरोइन का मुख्य घटक है। अफगान लोगों के अतीत और मौजूदा दुर्दशा में अनेक देशों का योगदान है, लेकिन अभी उनकी नियति तालिबान के हाथों में है। दो दशकों तक पाकिस्तान ने तालिबान की मेजबानी की और उन्हें सत्ता में वापसी की सुविधा प्रदान की, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वे अपने पूर्ववर्ती मददगार के भी खिलाफ जा सकते हैं, भले ही वह बाहरी दुनिया तक पहुंचने और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का प्रमुख स्रोत हो। तालिबान अपनी शर्तों पर दुनिया से निपटेंगे, चाहे वहां के लोगों के साथ जो भी सुलूक हो।

हिन्द स्वराज्य

सच्ची सभ्यता कौन सी ? (भाग-2)

गतांक से आगे...

बहुत सोचकर उन्होंने देखा कि सुख-दु:ख तो मन के कारण हैं। अमीर अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखने में आता है और गरीब सुखी देखने में आता है। करोड़ों लोग तो गरीब ही रहेंगे। ऐसा देखकर उन्होंने भोग की वासना छुड़वायी। हजारों साल पहले जो हल काम में लिया जाता था उससे हमने काम चलाया। हजारों साल पहले जैसे झोंपड़े थे उन्हें हमने कायम रखा। हजारों साल पहले जैसी हमारी शिक्षा थी वही चलती आयी। हमने नाश कारक होड़ को समाज में जगह नहीं दी; सब अपना-अपना धंधा करते रहे। उसमें उन्होंने दस्तूर के मुताबिक दाम लिये। ऐसा नहीं था कि हमें यंत्र वगैरा की खोज करना ही नहीं आता था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा कि लोग अगर यंत्र वगैरा की झंझट में पड़ेंगे, तो गुलाम ही बनेंगे और अपनी नीति को छोड़ देंगे। उन्होंने सोझ-समझकर कहा कि हमें अपने हाथ-पैरोंसे जो काम हो सके वही करना चाहिए। हाथ-पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है, उसी में तन्दुरुस्ती है। उन्होंने सोचा कि बड़े शहर खड़े करना बेकार की झंझट है। उनमें लोग सुखी नहीं होंगे। उनमें धूर्तों की टोलियाँ और वेश्याओं की गलियाँ पैदा होगी; गरीब अमीरों से लूटे जायेंगे। इसलिए उन्होंने छोटे देहातों से संतोष माना। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार के बनिस्बत नीति का बल ज्यादा बलवान् है। इसलिए उन्होंने राजाओं को नीतिवान् पुरुषों—ऋषियों और फकीरों—से कम दर्जे का माना। ऐसा जिस राष्ट्र का गठन है वह राष्ट्र दूसरों को सिखाने लायक है; वह दूसरों से सीखने लायक नहीं है। इस राष्ट्र में अदालतें थीं, वकील थे, डॉक्टर वैद्य थे। लेकिन वे सब ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये धन्धे बड़े नहीं हैं। और वकील, डॉक्टर वगैरा लोगों मे लूट नहीं चलाते थे; वे तो लोगों के आश्रित थे। वे लोगों के मालिक बनकर नहीं रहते थे। इन्साफ काफी अच्छा होता था। अदालतों में न जाना, यह लोगों का ध्येय था। उन्हें भरमाने वाले स्वार्थी लोग नहीं थे। इतनी सड़न भी सिर्फ राजा और राजधानी के आसपास ही थी। यों (आम) प्रजा तो उससे स्वतंत्र रहकर अपने खेत का मालिकी हक भोगती थी।

क्रमश: ...

मोदी यशोभूमि से 2024 के लिए राजनीतिक संदेश देने में सफल रहे

मृत्युंजय दीक्षित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी व कांफ्रेंस सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करते हुए इसी नवीन प्रांगण से 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से सुथर, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक सुनार, कुम्हार, जूते बनाने वाले, हथौड़ा और टुलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, मालाकर, कपड़े धोने वाले, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि कार्य कार्य करने वाले हुनरमंद भाई बहनों को 3 लाख तक बिना गारंटी ऋण देने की घोषणा की है। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग और 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और यह हुनरमंद अपने हाथों से जो उत्पाद तैयार करेंगे उन तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और उनकी मार्केटिंग में भी सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। प्रारम्भिक चरण में विश्वकर्मा योजना में 13000 करोड़ रुपये जारी किये हैं। यह योजना तीन लाख कामगारों के लिए विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक अनुपम उपहार है। यह माना जा रहा है कि इस योजना से 30 लाख परिवारों की वित्तीय स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस योजना से छोटे व्यवसायों और श्रमिकों को अपना व्यापार बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।

समाज के लाखों पारंपरिक कौशल वाले भाई-बहनों के लिए विश्वकर्मा योजना आशा की नई किरण बनकर आई है। इस योजना के माध्यम से भारत के स्थानीय सामान को वैश्विक बनाने में भी बहुत सहयोग मिलेगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र ने उपस्थित विश्वकर्माओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब बैंक आपको गारंटी नहीं मानता है तो मोदी आपको गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति व समाज के वंचित वर्ग के लोगों का मन जीतने की भी एक बड़ी पहल की है। यह पारंपरिक कार्य करने वाले अधिकतर कारीगर व शिल्पकार समाज के लोग इन्हीं वर्गों से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के इन वर्गो को सशक्त करने के लिए संकल्पवान है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का युग प्रारम्भ हुआ है और उसके पूर्व से भी समाज का यह वर्ग भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि के लोकार्पण और विश्वकर्मा योजना के शुभारम्भ के उपलक्ष्य पर गहरे राजनैतिक निहितार्थ वाला वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विशिष्ट कार्यशैली रही है कि अब तक उन्होंने जितने भी लोकार्पण कार्यक्रम किये हैं उन सभी अवसरों पर सर्वप्रथम वह श्रमिकों का सम्मान करते हैं व उनका मनोबल बढ़ाते हैं। यशोभूमि में भी उन्होंने सर्वप्रथम वहां काम करने वाले सभी प्रकार के विश्वकर्मा भाई बहनों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया।

प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में भारत मंडप और यशोभूमि जैसे सेंटर दिये हैं जो विकसित भारत का स्वप्न तो पूरा करेंगे ही साथ ही आगामी समय में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के वाहक बनेंगे। दोनों ही केन्द्रों पर विश्व भर के लोग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों और प्रदर्शनियों के लिए आएंगे इससे लाखों युवाओं को रोजगार और पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को भी काम मिलेगा। आगामी दिनों में भारत मंडप और यशोभूमि कांफ्रेंस पर्यटन के केंद्र बिंदु बनकर भी उभरने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगामी पर्वों को देखते हुए देशवासियों से लोकल उत्पाद खरीदने का एक बार फिर आग्रह करते हुए कहा कि जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप और भारत की मिट्टी की महक हो वही उत्पाद उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से सनातन संस्कृति का भी सन्देश दिया है क्योंकि हिंदू धर्म के आगामी दिनों में जितने भी पर्व व तिथियां आने वाली हैं उसमें जितनी भी छोटी से छोटी सामग्री व उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं वह सभी वंचित समाज के इन्हीं पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की मदद से ही बनाये जाते हैं। एक कालखंड बीच में ऐसा भी आ गया था कि हमारे पारंपरिक कारीगर व शिल्पकार जो उत्पाद बनाते व बेचते थे उस पर चीनी उत्पादों का दबदबा होता जा रहा था और हमारे कारीगर अपनी कला छोड़ने को मजबूर हो रहे थे।

नई विश्वकर्मा योजना से ऐसे ही कारीगरों की कला को नया जीवन मिलेगा। यह योजना पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू करने से पूर्व ही प्रारम्भ कर दी गई है और माना जा रहा है कि इन सभी राज्यों में इस योजना का प्रचार अवश्य किया जाएगा क्योंकि इस योजना के लाभार्थी चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

महिलाओं को टिकट देने से कतराने वाले नेता आरक्षण पर मुखर क्यों?

अभिरंजन कुमार

मनुष्य जाति की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और आधी पुरुषों की है, इसलिए यदि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में भागीदारी की बात की जाए, तो कायदे से महिलाओं और पुरुषों दोनों की भागीदारी आधी-आधी होनी चाहिए। लेकिन क्या इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण एक सही और न्यायसंगत तरीका है? क्या सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से इस भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र 75 साल बाद भी अपने नागरिकों को सबल बनाने और उन्हें सहज ही अवसरों की समानता मुहैया कराने में विफल साबित हुआ है? क्या अपनी इसी विफलता को छिपाने के लिए आरक्षण जैसे विवादास्पद, विभाजनकारी और नशीले उपचार पर इसकी निर्भरता दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है? संविधान लागू होते समय आरक्षण वाला जो उपचार एससी-एसटी समुदाय से शुरू हुआ, वह वाया ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस आज सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत के अटूट लगने वाले बांध को भी तोड़ते हुए 59.50 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। यानी अब इस देश में 100 में केवल 40 सीटें अनारक्षित बची हैं। इन बची हुई सीटों के लिए भी मारामारी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ओबीसी समुदाय की तरफ से जातिगत जनगणना और आबादी के हिसाब से आरक्षण दिये जाने की मांग ज़ोर पकड़ने लगी है। संसद और विधानसभाओं में भी एससी-एसटी के लिए पहले से ही आरक्षण है। अभी देश की 543 सीटों में से 131 सीटें एससी-एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। पंचायतों और नगर निकायों में भी 1992 से ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू है। बिहार जैसे राज्यों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत है। लेकिन इन तमाम आरक्षणों के बावजूद क्या इतने वर्षों और दशकों में किसी भी आरक्षित समुदाय का इतना उत्थान और सबलीकरण हो पाया है कि वे कह सके कि अब उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? हमारे लोकतंत्र के नक्कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह गूंजते इन्हीं सवालों के बीच संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की कवायद भी पिछले 27 साल से जारी है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने का सौभाग्य प्रचंड बहुमत के पहाड़ पर खड़ी मोदी सरकार के हिस्से में आया है। यद्यपि इस बिल के पास हो जाने के बाद भी अगली जनगणना और परिसीमन के संपन्न होने तक यह लागू नहीं हो पाएगा। एक और बड़ा सवाल यह कि किसी खास लोकसभा या विधानसभा सीट को महिलाओं या किसी खास वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित तो कर दिया जाएगा, लेकिन उस सीट पर केवल महिलाएं या उस खास वर्ग के लोग ही तो नहीं होते कि उस सीट का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अनिवार्य रूप से उन्हें ही दे दिया जाना चाहिए। संभव है कि वहां मतदाताओं का एक समूह भी आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों से इतर किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहता हो, लेकिन हम उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहे। ज़ाहिर है, इससे मतदाताओं की भी आकांक्षाओं और अधिकारों का दमन होता है। यदि वे महिलाओं के इतने ही बड़े हितैषी हैं, तो वे 33 प्रतिशत तो क्या, 50 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दे सकते हैं। इससे किसी का अधिकार भी नहीं मारा जाता और महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो जाता। और अगर राजनीतिक दल स्वेच्छा से ऐसी पहल नहीं करते, तो लोकसभा और विधानसभा सीटों को आरक्षित करने के बजाय एक बाध्यकारी कानून राजनीतिक दलों के लिए बनाया जाता, जिससे कि वे कम से कम एक तिहाई टिकट महिलाओं को देने के लिए बाध्य होते। अगर ऐसा हो सकता, तो किसी पुरुष को चुनाव लड़ने से रोके बिना ही संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपने आप बढ़ जाता। सवाल यह भी है कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद अपने उत्थान की चिंता में डूबी राजनीतिक पार्टियां किन महिलाओं को टिकट देंगी? क्या आम महिलाओं को या फिर ज्यादातर नेताओं की ही बहन-बेटियों, पत्नियों और पुत्रवधुओं को? अब तक के अनुभव से तो यह भी लगता है कि कुछ टिकट उन सज़ायाफ्ता नेताओं के परिवार की महिलाओं को भी बांट दिया जाएगा, जो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो चुके होंगे।

ऐतिहासिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम

अन्नपूर्णा देवी

नारी शक्ति को सम्मान और अधिकार देने की जो प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, उसे प्रमाणित करने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद प्रमाण हूं। झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने वर्ष 2019 में भारी अंतर से विजयी बनाकर मुझे पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाया। प्रधानमंत्री जी ने 11 महिलाओं को अपने मंत्रिपरिषद में स्थान दिया है। क्या यह नारी सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण नहीं है? मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि लगभग पूरा सदन इस विधेयक का समर्थन कर रहा है, और इस बात की लगभग गारंटी हो गयी है कि यह बिल सर्वसम्मति से पारित हो जायेगा। मैं इस परिस्थिति को देश में महिला आकांक्षाओं के चरमोत्कर्ष का प्रतिबिंब मानती हूं। तो क्या आज हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि महिला आकांक्षाओं को चरमोत्कर्ष के स्तर तक लानेवाले कारक कौन से हैं? इस विषय का ईमानदारी से विश्लेषण हो, तो इसका श्रेय भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही दिया जायेगा। इस विधेयक का समर्थन करने के बावजूद कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल कई प्रकार की आपत्तियां भी जता रहे हैं। इसमें उनका दोष नहीं। दरअसल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संवेदना के जिस स्तर पर जाकर महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने की सोच रहे हैं, वहां तक इन दलों की संकुचित दृष्टि जा ही नहीं पाती। इनकी सोच लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तक सीमित है, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं के नेतृत्व में नये, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना करते हैं। मोदी जी ने नारी आकांक्षाओं को कितना ज्यादा महत्व दिया है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि नये संसद भवन के ऐतिहासिक अनावरण के बाद महिला आरक्षण जैसे अति महत्वपूर्ण विधेयक को वहां की पहली संसदीय कार्यवाही के रूप में चुना गया। यह सही है कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रस्ताव पहले भी संसद में आये हैं, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि उनमें से कोई भी कानून नहीं बन सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बारे में कभी नीयत साफ नहीं रही, तो कभी तैयारी पूरी नहीं रही, तो कभी इसे पारित करवाने के लिए आंकड़े पक्ष में नहीं थे। लेकिन मोदी जी इस विधेयक को नारी शक्ति के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए, पूरी तैयारी के साथ लेकर आये हैं और इसलिए अब महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का हक लेने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया, और इसलिए उसे आज प्रधानमंत्री की इस युगांतरकारी पहल का श्रेय मिलना चाहिए। केवल श्रेय लेंगे? फिर राज्यसभा में पारित वह विधेयक वर्ष 2010 से 2014 तक लोकसभा में पड़ा रहा, वह पारित नहीं हुआ, और लोकसभा के भंग होने के साथ ही रद्द भी हो गया। तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। आधी आबादी के साथ किये गये इस सबसे बड़े धोखे के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। हम इतने बड़े विषय पर संकुचित नजरिये से नहीं सोचते। हम स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण और शहरी निकायों में कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन ऐसे आरक्षण की क्या उपयोगिता जो लंबे समय तक अमल में आ ही न सका।

आयुष्मान भारत से आयुष्मान भवः तक

डॉ. मनसुख मांडविया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के प्रावधानों के तहत सबको स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कोने—कोने में रह रहे लोगों तक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत बचाव और जागरूकता से लेकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्तर तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुनिश्चित हों, इसकी पूरी व्यवस्था हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर्स और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से की गई।

मोदी सरकार का लक्ष्य यह है कि देश के हर कोने में रह रहे जन—जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही आयुष्मान भवः अभियान लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर, 2023 को इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जन आरोग्य योजना को जन—जन तक ले जाने, हर किसी का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। कई तरह की बीमारियों की पहचान के लिए व्यापक स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। इनमें टीबी, हाइपरटेंशन, सिकल सेल डिजिज, मधुमेह आदि के लिए गांवों और शहरों में जांच अभियान चलाया जाना है।

आयुष्मान भवः का मूल लक्ष्य देश के 6.45 लाख गांवों और 2.55 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का है। ताकि लोगों के बीच इन योजनाओं को लेकर जागरूकता आए और वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। हमारे प्रेरणास्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय के सिद्धांत के अनुकूल इस अभियान को तैयार किया गया है ताकि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को मिल पाए। सबको स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें अंग दान अभियान चलाना शामिल है। साथ ही स्वच्छता अभियान और रक्त दान अभियान जैसे कई और गतिविधियां चलाई जाएंगी। इस अभियान के तीन मूल आधार हैं- आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान सभा और आयुष्मान मेला। इसके तहत समाज केंद्रित सोच के साथ जन—जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। आयुष्मान आपके द्वार का यह तीसरा संस्करण है। पहले के दो संस्करणों के सफलताओं को यह आगे बढ़ाएगा। इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में और तेजी लाई जाएगी। आयुष्मान सभा के जरिए गांवों के स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। आयुष्मान मेला के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चिंताओं का समाधान करने का काम किया जाएगा। आयुष्मान आपके द्वार अभियान की शुरुआत पूरे देश में 17 सितंबर को होगी और यह 31 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तकरीबन 60 करोड़ लाभार्थियों में से अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम इस अभियान के तहत होगा। ताकि कोई भी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं से अछूता न रहे। आयुष्मान सभा की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर, 2023 से होगी। 31 दिसंबर, 2023 तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर के गांवों और शहरों में इन आयोजन होगा। इसके जरिए मुख्य तौर पर जन—जन तक स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। जनभागीदारी से जनकल्याण की भावना विकसित करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी इसके तहत किया जाएगा। इसमें आयुष्मान कार्ड का वितरण, सूचीबद्ध अस्पतालों के बारे में जानकारी, आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी बनाने, स्क्रीनिंग सेवाएं, स्वास्थ्य चर्चा जैसी गतिविधियों का आयोजन होगा। इनमें स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के अलावा सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे।

आयुष्मान मेला का आयोजन हर हफ्ते गांवों के स्तर पर देश के सभी 1.6 लाख हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर्स पर होगा। साथ ही प्रखंड स्तर पर इसका आयोजन मेडिकल कॉलेजों के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा। इन मेलों के माध्यम से ईएनटी, आंख, मानसिक बीमारी आदि के लिए परामर्श और ईलाज की सुविधा एक बहुत बड़ी आबादी को मिलेगी। साथ ही लोगों में स्वास्थ्य को लेकर व्यापक जागरूकता का प्रसार होगा। इन सभी कोशिशों के माध्यम से हर गांव को आयुष्मान ग्राम पंचायत और हर शहरी वार्ड को आयुष्मान शहरी वार्ड बनाना है। ऐसा करके जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य के मामले में स्थिति बेहद मजबूत होगी। जिन गांवों में आयुष्मान कार्ड वितरण, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, स्क्रीनिंग और संक्रामक व गैरसंक्रामक बीमारियों के ईलाज के मामले में 100 प्रतिशत कवरेज होगा, उन्हें प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को जन—जन तक ले जाना सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ भारत की परिकल्पना का अंग है।

जी-20 में महिलाओं को सशक्त बनाने पर सर्वसम्मति

इंदीवर पांडे

वैश्विक राजनीतिक एवं कूटनीतिक परिदृश्य में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं, जो आशा और उन्नति की किरण साबित होते हैं। जी-20 नेताओं का वर्ष 2023 का नई दिल्ली घोषणापत्र भी ऐसी ही एक युगांतकारी घटना है, जो दुनिया भर में महिला-पुरुष समानता तथा लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। भारत की अध्यक्षता में जी-20 के नेताओं ने जी-20 महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का समर्थन करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्य समूह के गठन पर सहमति प्रकट की। यह उपलब्धि महिला-पुरुष समानता के महत्व को स्वीकार करने और वैश्विक स्तर पर महिला-पुरुष असमानताओं को दूर करने की तत्काल ध्यान देने योग्य आवश्यकता को गहन रूप से प्रतिध्वनित करती है।

भारत की अध्यक्षता में जी-20 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमृतकाल के विजन से प्रेरित रहा, जहां अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति को सराहा जाता है। इस विजन के आधार पर भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने पहली बार महिलाओं के विकास की जगह, अपना ध्यान महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित किया।

महिला-पुरुष समानता के पक्षधर दशकों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को वैश्विक एजेंडे में सबसे आगे लाने का प्रयास करते आए हैं। उनकी यह यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है और उन्हें इस रास्ते में अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ा है। अपने 2023 के घोषणापत्र में महिला-पुरुष समानता को केंद्रीय विषय के रूप में शामिल करने का जी-20 का सर्वसम्मत निर्णय दुनिया भर के नेताओं, सरकारों, सिविल सोसाइटी और हितधारकों के अथक प्रयासों और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दुनिया भर में महिलाओं के समक्ष आने वाले सबसे प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जी-20 और अतिथि देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और वक्ताओं के अलावा महिला पथप्रदर्शकों, उद्यमियों, नवोन्मेषियों, वैज्ञानिकों, जमीनी स्तर की महिला नेताओं तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को एक मंच पर लाया।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के प्रति आमूल-चूल बदलाव लाने वाला मार्ग, महिला उद्यमिता, इक्विटी और अर्थव्यवस्था के लिए लाभपूर्ण स्थिति, जमीनी स्तर सहित सभी स्तरों पर महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियां करना तथा जलवायु अनुकूलन कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में महिलाएं और लड़कियां- शामिल हैं। इन सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कौशल एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इन क्षेत्रों पर जी-20 एम्पॉवर पहल और डब्ल्यू-20 सहभागिता समूह द्वारा चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। इन बैठकों के मुख्य निष्कर्षों ने महिला-पुरुष समानता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धताओं को

प्रतिबिंबित किया, जिन्हें महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के वक्तव्य में अंगीकार किया गया और अंततः उसे जी-20 नेताओं के घोषणापत्र में पुख्ता स्थान दिया गया।

यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है! अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ सर्वसम्मति कायम करना और बातचीत करना कठिन कार्य रहा। विकासशील देशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे प्रायः विकसित देशों के साथ समान रूप से प्रतिध्वनित नहीं होते ।

प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जी-20 विमर्श में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और उद्यमिता के निष्कर्षों को जमीनी स्तर की महिला सामुदायिक नेताओं को शामिल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली प्लेबुक (या बेस्ट प्रैक्टिसेज प्लेबुक) की विरासत में स्थानीय स्तर पर महिला उद्यमियों और नेताओं का समर्थन नामक एक नया फोकस क्षेत्र जोड़कर इसे समर्थन दिया गया।

इन सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कौशल एक महत्वपूर्ण विषय रहा। डिजिटल जेंडर डिवाइड को पाटने की प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रतिबद्धता ने 2 से 4 अगस्त, 2023 तक आयोजित एमसीडब्ल्यूई के दौरान महिलाओं के डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभूतपूर्व टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म के शुभारंभ में योगदान दिया। इसके अलावा, इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कौशल मंच की पहुंच का विस्तार करने के वास्ते एमसीडब्ल्यूई में जी-20 देशों के साथ साझेदारियां स्थापित की गईं। यह प्लेटफॉर्म 120 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है और जी-20 देशों की लड़कियां और महिलाएं अपने करियर में उन्नति के क्रम में तेजी लाने के लिए डिजिटल स्किलिंग और अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों में अब अपना पंजीकरण करा सकती हैं।

एक अन्य ठोस परिणाम मेंटरशिप प्लेटफ़ॉर्म रहा। इसे एक वैश्विक नखलिस्तान माना जा सकता है, जहां जी-20 देशों की महिला परामर्शदाता अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को प्रशिक्षुओं के साथ साझा करती हैं, ताकि समस्त महिलाओं के सशक्तिकरण के सामूहिक विजन को साकार किया जा सके।

प्रेरक कहानियां वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए शक्तिशाली रोल मॉडल का काम करती हैं। पहली बार, भारत की अध्यक्षता में जी-20 एम्पॉवर वेबसाइट 9 देशों की 73 प्रेरक कहानियों के लिए एक ऐसा मंच बन गई, जिसने जी-20 देशों में कामयाबी का परचम लहराने वाली महिलाओं की शानदार यात्राओं को वृत्तचित्रित किया।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने स्वीकार किया कि नीतियों और रणनीतियों को सही मायने में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उनसे जुड़ी चर्चाओं में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते जी-20 विमर्श में जनभागीदारी की भावना को सम्मिश्रित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहल और सहभागिता समूहों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को रेखांकित करने वाले वॉकथॉन से लेकर फ्लैश मॉब तक के आयोजनों के माध्यम से 300,000 से अधिक नागरिकों को सफलतापूर्वक साथ जोड़ा। मंत्रालय ने स्थानीय महिला कारीगरों, शिल्पकारों और महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद और कौशल प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिससे भारत की जी-20 की अध्यक्षता वास्तव में जनता का कार्यक्रम बन गई।

जी-20 नेताओं का 2023 का नई दिल्ली घोषणापत्र केवल आशा की किरण भर ही नहीं है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान भी है। यह देशों को बयानबाजी से आगे बढ़ने और महिला-पुरुष समानता की दिशा में सार्थक कदम उठाने की चुनौती देता है।

भारत के पर्यटन स्थल

भारत विविधता में एकता का देश है जहाँ आपको हर तरह के लोग अपनी अलग संस्कृति, रीति-रिवाज आदि बिखेरते मिलेंगे। जैसे अनेक सब्जियों को मिलाकर एक स्वादिष्ट सब्जी बनती है, ठीक उसी तरह भारत में भी बहुत से धर्मों का समागम है जो मिलकर इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। उत्तर भारत में पर्यटन स्थल की कोई कमी नहीं है। आप भारत के पर्यटन स्थल देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ रंग-बिरंगी वादियाँ दिखेंगी तो दूसरी ओर समुद्र की ऊँची उठती लहरें। कही आसमान छूने वाले पहाड़ दिखेंगे तो कहीं खिलखिलाते बगीचे।बस ज़रूरत है ठहर कर इन्हें समटने की।

दिलवालों का शहर- दिल्ली

भारत की राजधानी दिलवालों की दिल्ली के नाम से मशहूर है। यह शहर यहाँ मौजूदा ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों, बाज़ारों आदि के लिए पूरे देशभर में विख्यात है। कहीं से भी आने वाला व्यक्ति दिल्ली अवश्य आता है और इसका ये कारण है कि उन्हें यहाँ का वातावरण मैत्रीपूर्ण लगता है। अगर आप कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं तो कमल मंदिर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पसंद होगी।

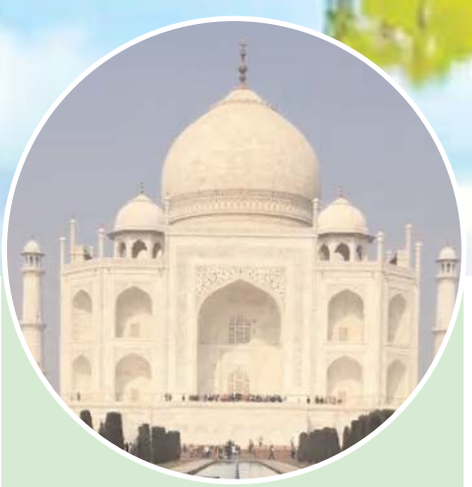

आगरा- ताजमहल का शहर

भारत दर्शनीय स्थल में आगरा का नाम बेझिझक लिया जाता है क्योंकि दुनिया के सात अजूबों में से एक अजूबा यहीं स्थित है। ताजमहल की असीम सुंदरता प्रेम की दास्तान बयान करती है। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेग़म मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। इसके पिछली तरफ यमुना नदी बहती है। यहाँ की एक और चीज़ मशहूर है और वो है स्वादिष्ट आगरा का पेठा, जिसका स्वाद आपकी

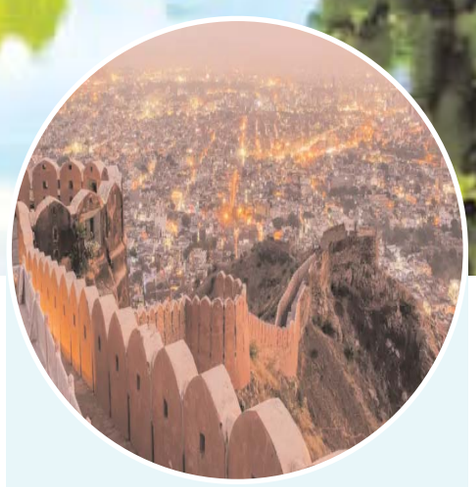

जयपुर -गुलाबी शहर

गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने वाला यह शहर राजस्थान में स्थित है। यह शहर विभिन्न प्रकार के किलों एवं प्राचीन इमारतों से भरा पड़ा है। भारत के पर्यटक स्थलों में जयपुर एक अभिन्न हिस्सा है। लोगों के बीच सबसे ज़्यादा प्रख्यात है हवा महल।अगर यहाँ आकर आपने हवा महल नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी है। राजस्थानियों के बीच रहकर आप खुद को.कभी बेगाना नहीं समझेंगे क्योंकि इनकी बोली में अपनापन है।

दार्जिलिंग- पहाड़ों की रानी

भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक दार्जिलिंग भी है जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। एक ओर मन को विलुप्त करने वाले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ हरे-भरे खूबसूरत चाय के बागान।यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ चाय का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अन्य आकर्षित स्थान हैं- टाइगर हिल, टॉय ट्रेन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और हैप्पी वैली टी एस्टेट।

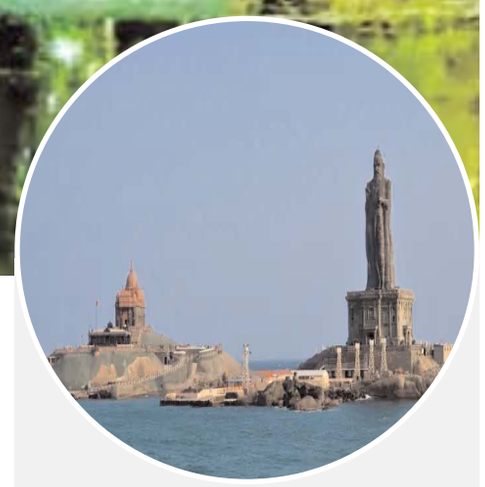

कन्याकुमारी-असीमित जल का क्षेत्र

कन्याकुमारी तीनों ओर से असीमित पानी से घिरा हुआ है। एक ओर अरब सागर है, दूसरी ओर हिन्द महासागर और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। यहाँ सूर्यास्त होने का नज़ारा एक अनोखा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।यहाँ आपको दक्षिण भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी। अगर आप दक्षिण भारतीय लजीज़ पकवानों के शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर आइए।

कश्मीर-भारत का स्वर्ग

कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इस जगह की हसीन वादियाँ आपको इस कदर वश में कर लेंगी कि आप बस इसे के होकर रह जाएंगे। बर्फ से ढके ऊँचे पहाड़ और पेड़-पौधे देखकर आप प्रकृति के रंग में रंग जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा की आप इन पत्तों की सरसराहट की भाषा समझ रहे हैं। झील से गिरती पानी की लहर आपको अपनी बाँहों में समेट लेंगी।

गोवा-छुट्टियों का पसंदीदा गंतव्य

यह शहर यहाँ मौजूदा बीचों के लिए लोकप्रिय है। आप यहाँ किसी भी मौसम में आकर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी को विश्राम दे सकते हैं। सुबह की शुरुआत पानी के खेलों से कीजिए, फिर शाम को ढलते सूरज को देखते हुए इसे कैमरे में कैद कीजिए, और रात को क्लब में पैर थिरकाते हुए बिताइए। आपको एक ही दिन में विभिन्न प्रकार के लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। आप यहाँ चर्च अथवा मंदिर में जाकर मन को कुछ पल की शांति प्रदान कर सकते हैं।

लेह/लद्दाख-बर्फ की चादर से घिरा शहर

जम्मू कश्मीर के पूर्वी भागों में स्थित लद्दाख लेह की राजधानी है और भारत के पर्यटन स्थल में से सबसे लोकप्रिय है। गर्मियों के मौसम में यह पर्यटकों से घिरी रहने वाली जगहों में से एक है जहाँ आप रास्तों को बर्फ़ की मोटी चादरों से ढका पाएंगे। इस जगह के दो पहलू हैं ङ्क पहला आपको आल्ची, थिकसे, लामायुरु आदि जैसे मठों के दर्शन करा कर आध्यात्मिकता में डूबो देगा और दूसरा आपको माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग आदि चीज़ें से रोमांचित कर देगा।

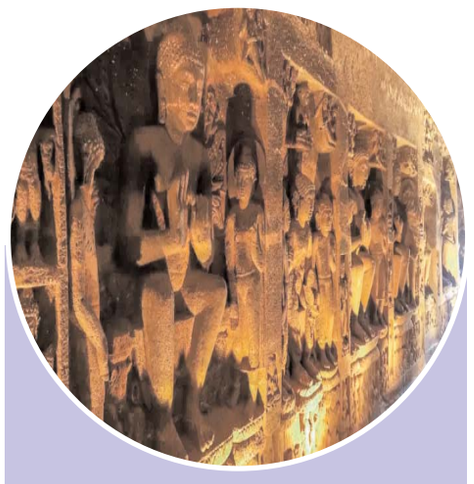

अजंता एवं एलोरा- प्राचीनता की शोभा

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित यह गुफाऐं बहुत-सी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। गुफा के अंदर आपको खूबसूरत बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। प्राचीन काल में बनाई गई ये गुफा कड़े परिश्रम का नतीजा है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में रखा है। भारत में पर्यटन स्थल लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करने में तत्पर रहते हैं। ऐसी अनोखी गुफा आपको मंत्रमुग्ध किए बिना मानेगी नहीं और आप यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।

वाराणसी -गंगा का पवित्र स्थल

धार्मिक स्थलों में से एक स्थल वाराणसी है जहाँ पूजा-पाठ और भक्ति के रंग में सब रंगे होते हैं। मंदिर की घंटियाँ भक्त को ईश्वर तक पहुँचाती है। गंगा की पवित्र धारा सब पर अपना आर्शीवाद बिखेरती चलती है। सूरज डूबते ही हर शाम यहाँ गंगा आरती होती है और पुजारियों के हाथ से घूमते बड़े-बड़े दिये जैसे शाम को जगमगा देते हैं।अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो यहाँ आकर अपनी भक्ति को पूरा कीजिए।

पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 100+ छोटे बड़े स्थानों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। उनमे से कुछ पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे।

भोरमदेव मंदिर

भोरमदेव मंदिर, कबीरधाम जिले के चौरागाँव में स्थित है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है और इसकी तुलना उड़ीसा के सूर्य मंदिर से भी की जाती है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। इस मंदिर को 1089 ई. में फणी नागवंशी शासक गोपाल देव ने बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से शिवलिंग की मूर्तियाँ हैं, इसके अलावा भगवान विष्णु के अवतार और काल भैरव, अष्टभुजी गणेश की नृत्य करते हुए मूर्तियाँ हैं।

चित्रकोट वॉटरफॉल

छत्तीसगढ़ का यह खूबसूरत जलप्रपात बस्तर जिले के जगदलपुर शहर से 38 किमी दूर इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसकी चौड़ाई 985 फीट और 95 फीट है, यह जलप्रपात घोड़े के नाल के आकार का है इस कारण इसे भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। यह मानसून के दौरान अपने चरम पर होता है मौसम के अनुसार यह अलग अलग खूबसूरत द्रश्य का निर्माण का करता है। अगर आपको नदियाँ, झरने और हरियाली पसंद है तो यह पर्यटन स्थल आपके लिये ही है।

गिरौधपुरी जैतखाम

गिरौदपुरी जैतखाम/धाम महानदी और जोंक नदियों के संगम पर गिरौधपुरी गाँव में स्थित है, बलौदाबाजार से 40किमी और बिलासपुर से 80 किमी दूर स्थित है। यह स्तंभ कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है, इस सफेद स्तंभ की आधुनिक वास्तुकला बहुत शानदार है ।

सबसे कमाल की बात यह है की यह कुतुब मीनार से भी ऊँचा है, इसकी ऊंचाई 77 मीटर (243 फीट) है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर (237 फीट) ऊंची है। इसमें 07 बालकनी बनाया गया है जिसके मदद से आप आसपास के सुंदर दृर्स्य का लुफ्त उठा सकते हैं।

लक्ष्मण मंदिर सिरपुर

लक्ष्मण मंदिर प्राचीन स्मारक है जो 'गहरे प्रेम' का एक अनूठा उदाहरण है। यह पति के प्यार का प्रतीक है,नागर शैली का यह मंदिर रानी वासाटा देवी, राजा हर्षगुप्त की स्मृति में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान 735-40 ईस्वी में बनवाया था। प्यार का यह अनोखा स्मारक ताजमहल से भी पुराना है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन मंदिर के अंदर शेषनाग में लक्ष्मणजी की मूर्ति है, इसीलिए इसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में से एक है जिसने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है।

मैनपाट

छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट, अपनी खूबसूरत वादियों और अनेको झरने, नदी नाले और आश्चर्य से भर देने वाले पर्यटक स्थलों से भरपुर है। मैनपाट की सुंदरता बारिश और ठंड के मौसम में चरम पर होती है। मैनपाट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 362 किलोमीटर और अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दुरी पर है।

तीरथगढ़ वॉटरफॉल

बस्तर जिले में जगदलपुर से लगभग 38 किमी दूर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा और बहार नदी में यह झरना स्थित है यह लगभग 300 फीट ऊंचा है और तीरथगढ़ वॉटरफॉल को छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। इस झरने के पास ही मंदिर है जो शिव जी और पार्वती माता को समर्पित है। इस झरने के आसपास हरे भरे वनस्पति है जो यहाँ के वतावरण को और भी खूबसूरत बनाते हैं।

कोटमसर गुफा

यह गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस गुफा की गहराई 54 से 120 फीट है और लंबाई 4500 मीटर है। कोटमसर गुफा के खोज का श्रेय प्रोफेसर शंकर तिवारी को जाता है, जिन्होंने 1958 में स्थानीय जनजाति के सदस्यों की मदद से इस गुफा की खोज की थी। अंदर की संरचना बहुत सुंदर है, गुफा के अंदर चूना पत्थर से बनी आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों पर रौशनी पड़ने पर कई तरह के अलग लग आकृति नज़र आती है। इस गुफा की सबसे अनोखी बात यह है की यहाँ आप अंधी मछली को देख सकते हैं।

ढोलकल गणेश

ढोलकल गणेश छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है यह दंतेवाड़ा से 18 किमी दूर, फरसपाल गाँव के पास बैलाडिला पहाड़ी में लगभग 3000 की ऊँचाई पर स्थित है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में से एक है, जिसे रहस्यमय पर्यटन स्थल मन जाता जाता है क्योंकि इतने ऊँचे पहाड़ी पर किसने इस गणेश की मूर्ति को रखा और क्यों रख अभी तक किसी को पता नही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भगवान गणेश की यह मूर्ति लगभग 1000+ साल पुरानी हैऔर इस मूर्ति को 9 वीं और 11 वीं शताब्दी के बीच नागवंशी शासकों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी।

जंगल सफारी रायपुर

रायपुर का जंगल सफारी एशिया में एकमात्र मानव निर्मित सफारी है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह शहर के केंद्र में बसा है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है।

यहाँ जाने के बाद आपको एक अलग अनुभव होगा यहाँ कई सारे जानवर खुले जंगल में विचरण करते हुए हुए नजर आयेंगे और आप पिंजरे के अंदर बंद होंगे। अगर आपको प्रकृति के करीब रहकर आनंदित होते हैं तो यहाँ आपको जरुर जाना चाहिए।

देवरानी जेठानी मन्दिर

देवरानी-जेठानी मंदिर मनियारी नदी के किनारे बिलासपुर से 29 किमी दूर तालागाँव नामक गाँव में स्थित है। देवरानी-जेठानी मंदिरों के लिए सबसे प्रसिद्ध छठी शताब्दी की रुद्र शिव प्रतिमा यहां स्थित है। यहां 4 वीं और 5 वीं शताब्दी के मंदिर हैं, जिन्हें देवरानी-जेठानी मंदिर कहा जाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे

नईदिल्ली। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 22-30 सितंबर 2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर हैं। 22 से 26 सितंबर तक अपनी न्यूयॉर्क में रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 78वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ग्लोबल साउथ के लिए भारत के समर्थन को ध्यान में रखते हुए, विदेश मंत्री एक विशेष कार्यक्रम इंडिया-यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट की मेजबानी करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे।

जेडीएस-भाजपा के बीच सीट बंटवारे का मुद्दा नहीं : देवेगौड़ा

बेंगलुरु। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत अभी से गर्म होने लगी है। जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आगामी आम चुनाव के लिए सत्तधारी कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के साथ मजबूत गठबंधन बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि उनके लिए जेडीएस और भाजपा के बीच सीट बंटवारे का कोई मुद्दा नहीं है। इसके लिए एचडी कुमारस्वामी भाजपा से बात करेंगे। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने कहा, यह मामला मेरे पास नहीं है। कुमारस्वामी गृहमंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। वहां पर दोनों के बीच चर्चा होगी। जहां तक भाजपा और जेडीएस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का सवाल है तो इस पर एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि जेडीएस-भाजपा गठबंधन में हम कम से कम चार सीटों पर लड़ेंगे।

सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू को भेजा समन

नईदिल्ली। गृह मंत्रालय द्वारा कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नए आरोपपत्र को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मामले के संबंध में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को समन जारी किया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यादव के अलावा रेलवे के पूर्व अधिकारियों को भी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। 12 सितंबर को, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में एक ताजा आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय से प्राप्त की गई थी। यह घटनाक्रम जुलाई में अदालत द्वारा बिहार के नेता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिए जाने के बाद हुआ। यह मामला कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है जब लालू 2004 से 2009 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में रेलमंत्री थे।

उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। याचिका में उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को समाप्त करने संबंधी बयान के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद ए. राजा, सांसद थिरुमावलवन, सांसद सु वेंकटेशन, तमिलनाडु के डीजीपी, ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस और अन्य को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि सनातन धर्म पर टिप्पणी के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इसमें तमिलनाडु और केरल के पुलिस महानिदेशकों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

अभिषेक पर ईडी को कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सांसद के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करे। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) खारिज नहीं की। ईसीआईआर प्राथमिकी के समान होती है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने ईडी को निर्देश दिया कि ईसीआईआर के आधार पर बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से पेश किए गए सबूत अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के वारंट के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी और सरकार प्रायोजित विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता के खिलाफ जांच जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े पड़ाव पार करता है : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की प्रतिबद्धता थी और उसने आज इसे पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि दशकों की बाधाएं थीं, लेकिन जब इरादा स्पष्ट होता है, तो हम परिणाम देखते हैं। उन्होंने बिल के पक्ष में वोट करने के लिए सांसदों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बिल का समर्थन किया। मोदी ने कहा कि मैं आज देश की सभी महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों हमने एक नया इतिहास बनते देखा। हमारा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों ने हमें यह इतिहास बनाने का अवसर दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित होने की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इसके (महिला आरक्षण बिल) राह में तरह-तरह की बाधाएं थी लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है तो परेशानियों को भी पार करके भी परिणाम लाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबके प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा और मजबूत कदम है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दोनों सदनों से पास होना, इस बात का भी साक्षी है कि जब पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है, तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, बड़े पड़ावों को पार करता है। उन्होंने कहा कि इसके पहले जब भी ये बिल (महिला आरक्षण बिल) संसद में आया तो लीपा-पोती हुई। सिर्फ नाम दर्ज कराए गए लेकिन निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। कल सब लोगों ने वोट तो दिया लेकिन उन्हें इस बात से तकलीफ

थी कि नारी शक्ति वंदन शब्द क्यों लाया गया है, क्या देश की महिलाओं को वंदन नहीं किया जाना चाहिए?....इस कानून ने साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार बहुत आवश्यक है।

आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने को देश की लोकतांत्रिक यात्रा का 'एक ऐतिहासिक क्षण' बताया। पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता को, बहन को, बेटी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। गुरुवार और बुधवार को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि-कोटि जनों ने हमें दिया है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं।

आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने संबंधी संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023' को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी।

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण! 140 करोड़ भारतीयों को बधाई।'' उन्होंने इस विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया और कहा कि इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। उन्होंने कहा, ''संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत कर रहे हैं। यह केवल एक विधेयक नहीं है, यह उन अनगिनत महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे राष्ट्र को बनाया है। भारत उनके लचीलेपन और योगदान से समृद्ध हुआ है।''

प्रधानमंत्री ने कहा, ''जैसा कि हम आज जश्न मना रहे हैं, हमें अपने राष्ट्र की सभी महिलाओं की ताकत, साहस और अदम्य भावना की याद आती है। यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज को और भी प्रभावी ढंग से सुना जाए।''

भाजपा महिला शाखा ने मोदी का स्वागत किया

संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के एक दिन बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला शाखा ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा मुख्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद थीं। इनमें सरकारी योजनाओं की लाभार्थी कई महिलाएं भी शामिल थीं। मोदी लाभार्थियों के एक समूह का अभिवादन करते हुए झुके। लाभार्थियों के इस समूह ने माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण एवं स्मृति ईरानी सहित पार्टी के कई नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।

राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में बताई दो कमियां, बोले-

जातीय जनगणना से ध्यान हटाने की कोशिश : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण विधेयक की कमियां गिनाईं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जातीय जनगणना से ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को अधूरा बताते हुए इसमें ओबीसी आरक्षण को शामिल करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि बिल को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है और इस बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया। बिल में दो चीजें संबंधित पाई गईं जिनमें एक की महिला आरक्षण से पहले जनगणना होगी और दूसरा परिसीमन करना होगा और इन दोनों को करने के लिए कई साल लगेंगे। महिला आरक्षण आज किया जा सकता है लेकिन सरकार यह करना नहीं चाहती है। सच्चाई यह है कि यह आज से 10 साल के बाद लागू होगा। डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि ये लागू होगा भी या नहीं। यह ध्यान भटकाने वाली राजनीति है।

2010 के बिल में ओबीसी कोटा न होने का अफसोस

राहुल गांधी ने कहा कि साल 2010 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए बिल में ओबीसी कोटा प्रदान नहीं किए जाने का उन्हें अफसोस है। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में राहुल ने पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि 2010 में यूपीए की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के तहत ओबीसी कोटा प्रदान नहीं किया गया था, इस पर राहुल गांधी ने कहा, 100% अफसोस है। यह उस समय किया जाना चाहिए था और अब हम इसे पूरा करके छोड़ेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, मैंने सिर्फ

यह सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? अगर नहीं हैं तो ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और है उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए। भाजपा को जनगणना और परिसीमन को हटाकर महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। जनगणना का लेकर हमने जो डाटा निकाला था उसे सार्वजनिक कर दें जिससे सभी को पता चल जाए कि ओबीसी कितने हैं और नई जनगणना जाति के आधार पर करें।

2024 से महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के विषय पर भाजपा बेनकाब: कांग्रेस

कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक को 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू करने और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने संबंधी संशोधनों को खारिज किए जाने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के असली इरादे बेनकाब हो गए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि भाजपा के रुख से यह स्पष्ट हो गया कि महिला आरक्षण विधेयक लाने की पूरी कवायद सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए थी।

खेल
प्रमुख समाचार

वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान

इस्लामाबाद। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस 15 सदस्यीय स्क्वॉड में नसीम शाह की जगह हसन अली को मौका मिला है। हालांकि, एक और चोटिल गेंदबाज हारिस रऊफ को भी टीम में शामिल किया गया है।

वहीं पाकिस्तान ने साथ ही उस्मान मीर के रूप में एक अतिरिक्त लेग स्पिनर को टीम में जगह दी है। उस्मान मीर ने इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। हसन अली के अलावा पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर को चुना गया है। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भी अपनी जगह बचाए रखने में कामयाब रहे हैं, जबकि फहीम अशरफ को इस टीम में जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम में बाबर आजम को कप्तान बनाया है। ओपनिंग जोड़ी के रूप में फखर जमान और इमाम उल हक को चुना गया है। बल्लेबाजों में सौद शकील और अब्दुला शफीक को भई शामिल किया गया है। विकेटकीपिंग का जिम्मा मोहम्मद रिजवान के कंधों पर होगा। वहीं स्पिन का जिम्मा शादाब खान और मोहम्मद नवाज को सौंपा गया है। स्पिन ऑलराउंडर्स के रूप में इफ्तिखार अहमद और उस्मान मीर को जगह मिली है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर के कंधों पर होगा।

टीम- फखर जमान, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, शादाब खान, उस्मान मीर, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 221 अंक टूटा निफ्टी 19,700 के नीचे

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों के कारण हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार उतार-चढ़ाव के बाद लगातार चौथे सत्र में लाल निशान पर बंद हुए। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 221 अंक टूटा। वहीं, निफ्टी में भी 68 अंको की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 221.09 अंक यानी 0.33 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 66,009.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,445.47 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,952.83 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 68.10 अंक यानी 0.34 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,674.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,798.65 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 19,657.50 तक आया।

भारत से यूरोपीय यूनियन को 43 फीसदी कम हो सकता है कार्बन उत्सर्जन का निर्यात

नईदिल्ली। भारत से यूरोपियन यूनियन को किए जा रहे 43 फीसदी निर्यात पर कार्बन उत्सर्जन को लेकर जारी नई व्यवस्था कॉर्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की वजह से खतरा मंडरा रहा है। इससे देश से यूरोपियन यूनियन को किए जाने वाले 37 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में पड़ सकता है। दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेड ब्लॉक के प्रस्तावित कॉर्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और अन्य ग्रीन पहलों के कारण ऐसा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के बाद भारत के प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के रेगुलेशन्स की वजह से भारत के विदेशी व्यापार में कई कैटेगरी को नुकसान पहुंच सकता है।

स्टेटिक ने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एनपीसीएल के साथ समझौता

नईदिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेवा प्रदाता स्टेटिक ने राष्ट्रीय राजधानी के पास ग्रेटर नोएडा में आवासीय परिसरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, समझौता ज्ञापन (एमओयू) भारतीय ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा बदलाव अभियान का नेतृत्व करने की दिशा में स्टेटिक के हालिया प्रयासों में शामिल है। स्टेटिक के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अक्षित बंसल ने कहा, '' हम न केवल भारत में सबसे बड़े ईवी चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि हम अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में भरोसेमंद ईवी चार्जिंग स्टेशन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर समाधान भी पेश कर रहे हैं।''

ऐपल बना भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक

नईदिल्ली। भारत में ऐपल का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक स्मार्टफोन के निर्यात में सैमसंग नंबर वन पर थी लेकिन ऐपल ने इसे पछाड़ दिया है। देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। द इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जून तिमाही में भारत से कुल 1.2 करोड़ स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जिसमें ऐपल की बाजार हिस्सेदारी 49 फीसदी रही। जबकि, सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी 45 फीसदी रही। पिछले साल अप्रैल से जून के बीच भारतीय स्मार्टफोन निर्यात में ऐपल की हिस्सेदारी सिर्फ 9 प्रतिशत थी। लेकिन अब ये हिस्सेदारी, वॉल्यूम के टर्म में कुल स्मार्टफोन निर्यात का लगभग आधा हिस्सा है। ऐपल पहले ही अपने प्रीमियम और सुपर प्रीमियम सेगमेंट के कारण वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक का टैग हासिल कर चुकी है।

मुद्रास्फीति कम करने की चुनौती

अजीत रानाडे

मुद्रास्फीति की दर अगस्त में घटकर 6.83 प्रतिशत हो गयी, जो पिछले महीने 7.44 प्रतिशत थी। यह अब भी छह प्रतिशत से ऊपर है, जिसे रिजर्व बैंक लक्ष्मण रेखा की तरह मानता है। वर्ष 2016 से मौद्रिक नीति का लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो गया। तब से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआइ के आधार वाली मुद्रास्फीति को दो से छह प्रतिशत रखने की कोशिश होती है। पिछले 12 महीनों में यह सातवीं बार हुआ है, जब मुद्रास्फीति की मासिक दर छह प्रतिशत से ऊपर चली गयी है। क्या यह रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति को परेशान करनेवाली स्थिति नहीं है? उन्हें मुद्रास्फीति को घटाने के लिए बाजार में मुद्रा के प्रवाह को कम करना होगा। लेकिन, उन्होंने ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति खुद कम हो जायेगी। आरबीआइ गवर्नर ने भी संकेत दिया है कि अभी कुछ समय तक महंगाई की दर ऊंची बनी रहेगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआइ) लगभग 450 अलग-अलग चीजों के औसत मूल्य के आधार पर तय किया जाता है, जो कि शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग होता है। इनमें से लगभग 49 प्रतिशत सामान खाद्य और इससे संबंधित सामग्रियों के होते हैं। इसलिए यदि खाने के सामान महंगे होंगे, तो कुल महंगाई भी ज्यादा होगी। सब्जियों, तिलहन, दालों, दूध और खाद्यान्नों की ऊंची कीमतों की वजह से खाने के सामानों की मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। इसे नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर पाबंदी या गेहूं, चावल, चीन और प्याज जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात पर भारी टैक्स लगाने जैसे उपाय किये गये हैं। इससे

निर्यात से लाभ की उम्मीद पाले बैठे किसानों की कमाई पर असर पड़ा है। जैसे, भारत ने वर्ष 2022 में 74 लाख टन उसना चावल का निर्यात किया, लेकिन अभी उस पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। भारत दुनिया के 40 प्रतिशत चावल का निर्यात करता है, और निर्यात नियंत्रण के उपायों के कारण दुनियाभर में खाद्यान्न की और भी कमी हो गयी है।

भारत के इस कदम से चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे आयातक देशों पर असर पड़ा है। फिलीपींस में एक मंत्री को चावल के महंगे होने के कारण इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। पर क्या इन उपायों से भारत में चावल सस्ता हुआ है? लगता तो नहीं, क्योंकि शायद टूटे चावलों का इस्तेमाल इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जा रहा है, जिसके निर्यात पर टैक्स लगाया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन के चावल की कीमतों का सूचकांक अगस्त में 9.8 प्रतिशत था, और अब वह पिछले 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह महंगाई भारत तक भी पहुंच सकती है। इथेनॉल की नीति डॉलर बचाने की कोशिश है, जिससे कि कच्चा तेल खरीदा जाता है। लेकिन, इसकी कीमत यदि देश में खाद्य सामग्रियों की महंगाई से चुकानी पड़े, तो खाद्यान्नों से ईंधन बनाने की नीति पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। वैसे, कच्चा तेल भी महंगा हो सकता है। रूस और सऊदी अरब के सप्लाई कम करने से, तेल की कीमत पहले ही 85 डॉलर के ऊपर हो चुकी है। इससे भारत के आयात पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और इस बात की संभावना है कि डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत घटेगी। इसकी भरपाई केवल सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के उम्मीद से अधिक निर्यात से हो सकती है। लेकिन, यह भी इतना सहज नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भी सुस्ती आ रही है। वैसे सॉफ्टवेयर उद्योग के संगठन नैसकॉम के अनुसार, मध्य और दीर्घ अवधि में भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं का भविष्य अच्छा प्रतीत होता है। इन सबके अलावा महंगाई को बढ़ाने में एक बड़ा कारण राजकोषीय घाटे का आकार होता है, जो भारत में बहुत ज्यादा है। इसे काबू में करने के सभी प्रयास नाकाम लग रहे हैं। बेशक, महामारी के समय घाटा बढ़ना ही था, क्योंकि सरकार को मुफ्त भोजन, रियायती कर्ज और बाजार में पैसे के प्रवाह को बनाये रखने के लिए आपात प्रबंध करने पड़े थे।

ठनी रहती है मेरी सिरफिरी हवाओं से.....

लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)को लोकसभा में पेश किया। वह पारित हो गया, राज्य सभा में भी बिल पारित हो गया अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाने का रास्ता साफ हो जाएगा जिसमें वर्तमान लोकसभा की कुल सीटों में एससी वर्ग की महिलाओं के लिये 28, एसटी वर्ग के लिये15 तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिये 138सीटें आरक्षित होंगी। हालांकि विपक्ष ने ओबीसी वर्ग के लिये भी आरक्षण यानि आरक्षण के भीतर भी आरक्षण के लिये आवाज़ उठाई तथा तत्काल ही आरक्षण लागू करने दबाव भी बनाया था पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत यह संभव नहीं था। वैसे लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद हैं। फिलहाल तो महिला आरक्षण झुनझुना ही होगा क्योंकि बिल पारित होने के बाद जनगणना, परिसीमन के बाद ही महिलाओं के लिये सुरक्षित सीटें तय होंगी,2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का प्रावधान लागू हो सकेगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि ज़ब यह प्रावधान 2029 में लागू होना था तो विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी?यह दिसंबर में होने वाले नियमित सत्र में भी हो सकता था... वैसे विपक्ष का कहना है कि नवम्बर में होनेवाले 5 राज्यों के विस चुनाव में महिला मतदाताओं को अपनी और आकर्षित करने भाजपा का एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा माना जा रहा है।वैसे महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ था।

उस समय एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था।राजीव गाँधी, अटलजी,नरसिम्हा राव के समय भी पहल हुई थी,लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था।बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण का प्रस्ताव था।इस 33 फीसदी आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए उप-आरक्षण का प्रावधान था।लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था।नये बिल में भी प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए।आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के ज़रिये आवंटित की जा सकती हैं।इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण ख़त्म हो जाएगा।

अयोध्या में राम लला के दर्शन से मुंडन तक....

छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बनेगा। भूपेश सरकार के भांचा राम,कौसल्या मंदिर,राम वनपथ गमन और कृष्ण कुंज योजनाओं का काट श्रीराम पर एकाधिकार जताने वाली भाजपा के पास नहीं है, तभी तो छग आने वाले भाजपा के बड़े नेता मोदी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाने,भूपेश सरकार की कमियां बताने की जगह हिंदुत्व पर ही बोलना उचित समझते हैं। कांग्रेस छोड़कर,भाजपा में शामिल होनेवाले असम के सीएम ने छग में हिंदुत्व का एक अलग मुद्दा उछाल दिया है और उसका जवाब मिलने पर भाजपाईयों को कुछ सूझ नहीं रहा है।हिंदुत्व के मुद्दे पर दो राज्यों के सीएम आपस में भिड़ गए हैं। पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने छग के सीएम को हिंदू होने की पुष्टि के लिए राहुल और सोनिया गांधी को अयोध्या ले जाने की चुनौती दी ।तब छग के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है।सीएम भूपेश बघेल ने हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर दिया है?असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व सरमा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जरा भी हिन्दू हैं तो राहुल गांधी को रामलला के मंदिर लेकर जाओ। यदि चुनावी हिन्दू मात्र नहीं हैं तो राहुल को अयोध्या लेकर जाएं।तब छग के सीएम भूपेश बघेल ने असम के सीएम की चुनौती पर जवाब देते हुए कहा कि %%असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा हिंदू हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं...हमारे हिंदू धर्म के आधार पर माता या पिता की मृत्यु हो जाने आग देने वाले पुत्र को बाल(मुंडन संस्कार)देना होता है।लेकिन पीएम मोदी तो सर मुड़ाए ही नहीं..तो सीएम हिमंत से कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी का मुंडन करवा लें....माता के निधन के बाद अभी तक नहीं कराया है। अगर वो मुंडन कराएंगे तो मैं हिमंत बिस्वा सरमा को हिंदू मानूंगा %% इधर विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व बड़ा चुनावी मुद्दा होगा ऐसा लग रहा है।छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।भाजपा,कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है तो कांग्रेस भी सत्ता में जमे रहने के लिए जोर लगा रही है।कांग्रेस लगातार भगवान राम के ननिहाल के रूप में छत्तीसगढ़ को देश में पेश कर रही है।भगवान राम के वनवास के समय छग के जिन स्थानों पर उनका ठहरना हुआ था उन इलाकों को राम वन पथ गमन के रूप में विकसित किया जा रहा है।वहीं भाजपा,कांग्रेस सरकार पर गौ माता के नाम पर राजनीति करने आरोप लगा रही है।

छग में महिला विधायकों का प्रतिशत अधिक....

देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण के बिल की चर्चा तेज है ऐसे में यह चर्चा भी लाजिमी है कि पूरे देश में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इसमें खास बात है कि यहां कांग्रेस की भूपेश सरकार के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए। जिसमें 3 महिला प्रत्याशी को टिकट दिया। ये सभी अपने-अपने विधानसभा चुनाव में विजयी हुईं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों पर 16 महिला विधायक हैं।वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 सीट में से 13 सीटें महिलाओं ने जीत हासिल की थी। इनमें विधानसभा में

अंबिका सिंहदेव (बैकुंठपुर), उत्तरी गणपत जांगड़े (सारंगढ़), रेणु जोगी(कोटा), डा. रश्मि सिंह (तखतपुर), इंदू बंजारे (पामगढ़), शकुंतला साहू (कसडोल), अनिता शर्मा (धरसींवा), डा लक्ष्मी धुर्व (सिहावा), रंजना साहू (धमतरी), संगीता सिन्हा (संजारी बालोद), अनिला भेड़िया(डौंडीलोहारा), ममता चंद्राकर (पंडरिया) और छन्नी साहू (खुज्जी) चुनकर पहुंची थीं। बाद में तीन उपचुनाव के बाद दंतेवाड़ा में देवती कर्मा, खैरागढ़ में यशोदा वर्मा और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी समेत महिला विधायकों संख्या 16 हो चुकी है।एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं में कुल सीटों के मुकाबले छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 14.4 प्रतिशत महिला विधायक हैं। जो कि दूसरे राज्यों की तुलना में सर्वाधिक थीं। हालांकि हरियाणा में अब महिला विधायकों की संख्या घटकर आठ हो गई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भागीदारी 14.4 प्रतिशत से बढ़कर 17.7 प्रतिशत हो गयी है। अब छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से आगे है।छत्तीसगढ़ कुल में 90 सीट में 16 महिला 17.77प्रतिशत,मप्र में 230 सीट में 21 महिला 9.13 प्रतिशत,उत्तर प्रदेश में 403 सीट में 47 महिला 11.66 प्रतिशत,ओडिशा 147 सीट में 15 महिला 10.20 प्रतिशत हैं ।

फ़िल्म जवान के बहाने सरकार पर निशाना?

गौरी और शाहरुख़ खान की फिल्म जवान कोई एक कहानी नहीं है,बल्कि कई छोटे-छोटे मुद्दों को एक पैकेज के रूप में पेश किया गया है। भ्रष्टाचार समेत ऐसे कई मुद्दे शामिल किए गए हैं।जैसे विपक्ष मोदी सरकार पर हमला करता है,उसी एजेंडे को जवान आगे बढ़ा रही है। इसी वजह से इस फिल्म का राजनीतिक विश्लेषण किया जा रहा है। फिल्म जवान में दिखाया गया है कि कैसे सरकार कुछ खास कारोबारियों के लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर देती है. दूसरी तरफ गरीब किसानों को कुछ हजार रुपए के लोन के लिए परेशान किया जाता है। एक करोड़पति कोऑडी जैसी कार के लिए महज 8 फीसदी में लोन मिल जाता है,जबकि किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 13 फीसदी की दर से लोन लेना पड़ता है।फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति का 40 हजार करोड़ का लोन सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाता है।इस फिल्म में गोरखपुर ऑक्सीजन कांड की कहानी भी दिखाई गई है. 10 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 70 से ज्यादा इंसेफेलाइटिस पीड़ित बच्चों की मौत हो गई थी। इसका ठीकरा मेडिकल कॉलेज के डॉ कफील खान के सिर फोड़ दिया गया। उन्हें आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया।लेकिन दो साल के बाद कोर्ट ने उन्हें इस केस से बरी कर दिया था. फिल्म में एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा का किरदार डॉक्टर कफील से प्रेरित है।उन्हें बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताकर जेल भेज दिया जाता है। इस फिल्म में रक्षा घोटाले की कहानी भी दिखाई गई है।इसमें दिखाया जाता है कि कैसे सरकार के एक बड़े नेता और उनके करीबी सहयोगियों की मदद से एक ऑर्म्स डीलर खराब हथियारों की सप्लाई करता है।इसकी वजह से एक मिशन में कई जवान शहीद हो जाते हैं। वैसे तो रक्षा घोटालों का एक लंबा इतिहास रहा है,लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो कांग्रेस राफेल डील को लेकर मोदी सरकार को हमेशा कठघरे में खड़ा करती रही है।

और अब बस....

- कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गाँधी ने भिलाई के एक कार्यक्रम में भौंरा चलाकर सभी को आश्चर्य चकित कर दिया...?
- डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव के हर बयान को भाजपा क्यों लपक रही है... ?
- महादेव ऐप के संचालक की शादी में क्या छग से भी पुलिस अफसर गये थे.. ?
- दूसरी बार गृह मंत्री तथा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का छग दौरा रद्द हो गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा की परिवर्तन यात्रा को जनता ने नकार दिया: बैज

रायपुर। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि जनता भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल ही नही होना चाहती, पूरी ताकत देश भर से केन्द्रीय नेताओं को बुलाने के बाद भी भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में होने वाली सभा में सामान्य नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नही एकत्रित हो रही है।छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में अवश्यंभावी हार, भाजपा के प्रति भयंकर आक्रोश और भूपेश सरकार को मिलते अपार जन स्नेह के भय से भाजपा के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ में आयोजित परिवर्तन यात्रा व अन्य कार्यक्रमों में आने से कतरा रहे हैं। भाजपा नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार दूसरी बार रद्द हुआ है। पिछली बार जब अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने छत्तीसगढ़ आए थे तब 1000 लोगों की क्षमता वाला हॉल भी पूरी तरह भर नहीं पाया था।उसके बाद दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए अमित शाह आने वाले थे मगर सम्मानजनक भीड़ नहीं जुट पाने के कारण अमित शाह ने अपना दौरा रद्द कर दिया और भाजपा द्वारा मौसम को बहाना बना दिया गया। उसके बाद किरकिरी को संभालने के लिए भाजपा द्वारा स्मृति ईरानी के परिवर्तन यात्रा में शामिल होने का जुमला छोड़ा गया मगर स्मृति ईरानी भी जगदलपुर तक पहुंची।

गैंगरेप: कांग्रेस सरकार के नाकारापन का शर्मनाक: रंजना

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासनकाल में मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं तक की अस्मिता कहीं सुरक्षित नहीं रह गई है। श्रीमती साहू ने कहा कि राजधानी के बीचो-बीच जयस्तंभ चौक के करीब एएसपी दफ्तर के पास मल्टीलेवल पार्किंग में एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के नाकारापन का एक और शर्मनाक उदाहरण बताया है। श्रीमती साहू ने कहा कि प्रदेश में एक ओर कांग्रेस सरकार महिला समृद्धि सम्मेलन करके राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर राजधानी में वहशी दरिंदों ने एक किशोरी की अस्मिता को लहूलुहान कर दिया लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सबने मुँह में दही जमा रखा है। यह विडंबना ही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा महिला समृद्धि सम्मेलन की नौटंकी में शामिल होने आईं थीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में महिलाओं की बदतर हालत से आँखें मूंदे रहीं।पिछले लगभग एक माह में प्रदेश की राजधानी में और इससे लगे स्थानों पर महिलाओं के साथ हो रहीं लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार कर रखा है, लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार को जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। वह प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बेहतरी और महिला सुरक्षा के खोखले दावे कर रहे हैं जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि रोज अखबार बलात्कार की घिनौनी घटनाओं की खबरों से रंगे रहते हैं।

धान खरीदी में केंद्र का योगदान शून्य : शुक्ला

रायपुर। धान खरीदी पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार का धान खरीदी में कोई योगदान नहीं है।

धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेंड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रूपये, देश ही नही दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने के लिये जबरिया वाहवाही लेने के लिये राजनीति कर रहे है। पिछले वर्ष 107 लाख मीट्रिक धान की खरीदी कांग्रेस सरकार ने किया था। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में रमन सरकार के द्वारा इसका आधा धान ही खरीदा जाता था। इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र का राज्यों से चावल और अन्य अनाज खरीदना और राज्य का अपने किसानों से धान खरीदना दोनों अलग-अलग योजना है। राज्य अपने किसानों को उसकी उपज की पूरी कीमत देने अपने संसाधनों से धान की खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ के किसानों से भूपेश सरकार ने 2660 रू. में धान खरीदा है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि ने तो किसानों को 1000-1200 में धान बेचना पड़ता है।

मोदी राज में आम जनता पर कर्ज हुआ दुगना: वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि देश के आमजनता की लगातार गिरती आमदनी और बढ़ते उधारी का मुख्य कारण मोदी निर्मित आर्थिक आपदा है। 100 दिन में

महंगाई कम करने का वादा करके केंद्र में बैठी मोदी सरकार के महालूट के चलते ही देश की जनता की पारिवारिक बचत ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर, जीडीपी के मात्र 5.1 प्रतिशत पर आ गई है। 2020-21 में शुद्ध पारिवारिक बचत कुल जीडीपी का 11.5 प्रतिशत था, जो 2021-22 में घटकर 7.2 प्रतिशत पर आ गया था और अब तो ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। मोदी सरकार ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भारी भरकम टैक्स के दायरे में लाकर और अनियंत्रित मुनाफाखोरी करके न केवल आम परिवारों का बजट बिगड़ा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। मोदी सरकार ने देश के संसाधन, सार्वजनिक उपक्रम, देश के खनिज, कोयला सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट अडानी के हवाले कर दिए। एसबीआई और एलआईसी का पैसा भी मित्र पर लुटा दिए। मोदी से पहले देश के कुल 14 प्रधानमंत्रीयों ने 67 साल में कुल मिलाकर केवल 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने अकेले ही 100 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेकर देश पर कुल कर्ज का भार 2014 की तुलना में तीन गुना अधिक कर दिया है। 2014 में अदानी की कुल संपत्ति लगभग 50 हजार करोड़ की थी।

शराब तस्करी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करें: लखमा

रायपुर। आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री लखमा आज नवा रायपुर के आबकारी आयुक्त

कार्यालय भवन के सभाकक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।आबकारी मंत्री श्री लखमा ने कहा कि अवैध शराब बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर, सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए सुनियोजित कार्य-योजना के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने बैठक में अन्य राज्यों से आने वाले मदिरा विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण, राज्य में अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावटी शराब विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने कहा। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय टोल फ्री नंबर 14405 पर प्राप्त शिकायतों तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर शिकायतों के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।आबकारी मंत्री श्री लखमा ने बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का विभाग में पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टि में रखते हुए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित आबकारी जांच चौकियों में सीसीटीवी कैमरों के सर्विलांस में वाहनों की सघन जांच करें।

भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है: पांडेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद (राजनांदगाँव) संतोष पांडेय ने कहा है कि भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसी के समानांतर महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक को प्रस्तुत करना और संसद में पारित कराना दृढ़निश्चयी, संकल्पवान नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। श्री पांडेय गुरुवार की देर रात लोकसभा में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता व महिला आरक्षण पर अपने विचार रख रहे थे।

भाजपा सांसद श्री पांडेय ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा है, वह पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रही है। हँसी-मजाक में पहले कहा करते थे कि अगर इस देश की चले, तो लोग कटोरा लेकर चंद्रमा पर भी चले जाएँ। यह मजाक की बात हुआ करती थी, पर उस समय स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थीं। हम सब उन स्थितियों से अवगत हैं। इस देश को सपेरों का देश, लकड़हारों का देश तक कहा गया। श्री पांडेय ने कहा कि आज जो इस देश ने अपनी उच्च स्थिति को अर्जित किया है, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। आज हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत को क्यों भविष्य की महाशक्ति कहा जा रहा है? महाशक्ति बनने की ओर भारत जा रहा है। दुनिया में चंद्रमा पर फतह के लिए सबसे सस्ते जिस चंद्रयान-3 मिशन को भारत ने जिस अंदाज में पूरा किया, उसने दुनिया के विकसित राष्ट्रों की आँखें खोलकर रख दी हैं।

भाजपा सांसद श्री पांडेय ने महिला आरक्षण संबंधी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर कहा कि आज विपक्ष लाख सिर पटके, चंद्रयान-3 मिशन की अवधारणा के समानांतर जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया और हम सबने मिलकर उसे पारित किया, यह वास्तव में निस्संदेह जब दृढ़निश्चयी, संकल्पवान नेतृत्व होता है।

बघेल प्रदेश की सेवा के लिये नहीं गांधी परिवार की सेवा के लिये मुख्यमंत्री बने हैं : कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा के द्वितीय चरण में शामिल होकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र के करतला में आयोजित आम सभा को संबोधित किये इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है इससे पहले भी 2003 में भी बीजेपी ने यात्रा निकली थी और कांग्रेसी कुशासन को जड़ से उखाड़ फेंका था। आज इतिहास फिर स्वयं को दोहरा रहा है और एक बार फिर परिर्वतन यात्रा निकली है और इस बार भी सीएम भूपेश बघेल वाली

कांग्रेसी कुशासन को हम जड़ से उखाड़ फेकेगें। छत्तीसगढ़ के वासियों ने बीजेपी के 15 वर्ष का विकास देखा है किन्तु प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पांच सालों में प्रदेश के विकास को गर्त पर ढ़केल दिया है। इस यात्रा में हमें प्रदेश का विकास ढुंढने से नहीं मिल रहा है तो भूपेश बघेल कौन से विकास की राग अलापते है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता के सेवा के लिये नहीं बल्कि गांधी परिवार की सेवा के लिये मुख्यमंत्री बने है। जिस तरह से प्रदेश में शराब माफिया, कोल माफिया, रेत माफिया, आयरन माफिया, सिंमेट माफिया, गांजा तस्करों का बोलबाला है इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में पुरी तरह से स्वतंत्र केवल इन्हीं लोग है और यह कार्य बिना संरक्षण के होना असंभव है। कांग्रेस सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने कम समय में करोड़ों रु का घोटाला किया है।

सरकार को शराब का नशा चढ़ गया : शालिनी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और पूर्व संसदीय सचिव चम्पादेवी पावले ने कांग्रेस सरकार के मंत्री कवासी लखमा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि मंत्री लखमा अपने बयान से जिस तरह छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इसका खामियाजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा नेत्रियों ने कहा कि गंगाजल की सौगंध लेकर पूर्ण शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आ गई। शराबबंदी के वादे पर प्रदेश की मातृ-शक्ति से धोखाधड़ी करने वाली कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार को अब इस शराब का नशा चढ़ गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती वर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राजपूत व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती पावले ने कहा कि मंत्री लखमा जो कह रहे हैं कि वह जहाँ जाते हैं वहाँ शराब दुकान खोलने की मांग आती है, तो क्या लखमा यह कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता शराबी है। प्रदेश की भूपेश सरकार की शराब के कारण हजारों बहनों का सुहाग उजड़ गया।

भूपेश की लबरा सरकार उन्हीं के डबरों में डूबेगी : बृजमोहन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की लबरा भूपेश सरकार यहां के डबरों में डूब जाएगी। फिर चाहे वह सड़क के डबरे हो या घोटालों के, अपराध के डबरें हो या अव्यवस्था के, इस सरकार का डूबना तय है। डबरा में तो बहुत पानी होता है, इस सरकार को तो चुल्लूभर पानी में डूब जाना चाहिए। वे गांधी चौक में परिवर्तन यात्रा के दौरान उमड़ी विशाल जन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने शोषण किया, लोग

आंसू पीते रहे, अब तक छत्तीसगढ़ की बेटियों से दिनदहाड़े बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब प्रदेश में अपराध न हो, भ्रष्टाचार ना हो। भाजपा की परिवर्तन यात्रा ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार है। परिवर्तन यात्रा आज धमतरी, पाटन, भाटापारा, कुकरेल, नगरी से भी गुजरी। जबरदस्त उमड़ी भीड़ ने जताया कि कांग्रेसी सरकार की जमीन हिल रही है। नगरी के राजाबाड़ा में भी महती आम सभा हुई। इसमें भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धमतरी की विधायक रंजन दीपेंद्र साहू, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा, और धमतरी जिला अध्यक्ष शशि पवार ने भी संबोधित किया।

प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अरुण साव ने जताया आभार

रायपुर/बिलासपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव प्रदेशवासियों के विकास के लिए सदैव प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ के हर मुद्दे पर केंद्र सरकार से सामंजस्य स्थापित कर प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर अरुण साव के प्रयासों को रेल मंत्रालय ने रेल स्टापेज सुविधा को हरी झंडी प्रदान की है। सांसद अरुण साव के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 15159-15160 छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, 18257-18258 बिलासपुर चिरमिरी एक्सप्रेस का करगी रोड स्टेशन में और बिलासपुर चिरमिरी एक्सप्रेस का बेलगहना स्टेशन में ठहराव निर्धारित हुआ है। साव ने कहा कि ट्रेन का ठहराव होने से अब क्षेत्रवासियों को जहां सुविधा प्राप्त होगी। वहीं नौकरी पेशा व व्यापारियों को ट्रेन का लाभ मिलेगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.